Website : www.mantrabharat.com
जुनून है सच लिखने का
E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 10
अंक : 275
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
शनिवार, 11 अक्टूबर, 2025

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 नागपुर में बनेगा विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर...
4 बुर्का-हिजाब बैन, मस्जिदों पर ताले! ...
7 पुलवामा शहीद के बेटे का हरियाणा ...

संक्षिप्त न्यूज

नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम क्या रखा जाए? चर्चाओं के बीच आया अजित पवार का बड़ा बयान

मुंबई(संवाददाता) | नवनिर्मित नवी मुंबई हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर चल रही बहस के बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि फिलहाल सबसे जरूरी है कि एयरपोर्ट पूरी तरह कार्यरत हो जाए. उन्होंने कहा कि उड़ान और लैंडिंग लगभग 45 दिनों में शुरू होने की उम्मीद है. पवार ने कहा कि स्थानीय नागरिकों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और इस पर मुख्यमंत्री पहले ही जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर चुके हैं.

अजीत पवार ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता फिलहाल एयरपोर्ट को संचालन योग्य बनाना है ताकि मुंबई क्षेत्र की हवाई सेवाओं पर दबाव कम हो सके. उन्होंने कहा कि एक बार हवाई अड्डा चालू हो जाने के बाद, नामकरण को लेकर उचित और सर्वसम्मत निर्णय लिया जाएगा. पवार ने आश्वासन दिया कि इस प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की भावनाओं और परंपराओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

इसी बीच पुणे में आयोजित एक 'परिवार मिलन' कार्यक्रम में अजीत पवार ने कहा कि ऐसे आयोजनों से सरकार को जनता की वास्तविक समस्याओं को समझने का मौका मिलता है. उन्होंने बताया कि इसमें कार्यकर्ता, महिलाएं और समाज के अलग-अलग वर्गों के लोग भाग लेते हैं. पवार ने कहा कि 'समस्याओं को केवल सुनने और खुद देखकर समझने में बड़ा फर्क होता है, इसलिए ऐसे कार्यक्रमों का महत्व बढ़ जाता है.'

अजीत पवार ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आम लोगों से सीधे संवाद के ज़रिए नीतियों को और अधिक जनसुलभ बनाया जाए. उन्होंने कहा कि चाहे एयरपोर्ट का नामकरण हो या मध्यम वर्ग की परेशानियां, जनता की भागीदारी से ही समाधान निकलता है. पवार ने भरोसा दिलाया कि महाराष्ट्र सरकार हर मुद्दे पर जनता की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेगी और विकास कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखेगी.

पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू होगा एसआईआर

चुनाव आयोग ने बताया किन राज्यों से होगी शुरुआत

नई दिल्ली। चुनाव आयोग देश में चरणबद्ध तरीके से मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम शुरू कर सकता है। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत उन राज्यों से हो सकती है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आयोग उन राज्यों में मतदाता सूची संशोधन अभियान नहीं चलाएगा जहां स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं या हो रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव मशीनरी, निकाय चुनाव में व्यस्त है और इसके चलते वे एसआईआर पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे।

इन राज्यों में शुरू हो सकती है एसआईआर की प्रक्रिया

गौरतलब है कि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन पांच राज्यों के अलावा पहले चरण में कुछ अन्य राज्यों में भी एंईं की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। बिहार में एसआईआर का काम पूरा हो गया है, जहां 30 सितंबर को लगभग 7.42 करोड़ नामों वाली अंतिम सूची प्रकाशित की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को कहा कि सभी राज्यों में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण शुरू करने का काम चल रहा है और इसे शुरू करने पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग द्वारा लिया जाएगा।

राज्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश अधिकारियों के अनुसार, चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने इस महीने की शुरुआत में एक सम्मेलन में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों (सीईओ) से अगले 10 से 15 दिनों में एसआईआर शुरू करने के लिए तैयार रहने को कहा था। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने राज्यों की मतदाता सूचियों को अंतिम एसआईआर के बाद प्रकाशित रखें।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 2008 की मतदाता सूची है, जब राष्ट्रीय राजधानी में अंतिम बार गहन पुनरीक्षण हुआ था। उत्तराखंड में, अंतिम एसआईआर 2006 में हुआ था, और उस वर्ष की मतदाता सूची अब राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर है। अधिकांश राज्यों में मतदाता सूची की अंतिम एसआईआर 2002 और 2004 के बीच थी। एसआईआर का प्राथमिक उद्देश्य अवैध मतदाताओं के जन्म स्थान की जांच करके उन्हें मतदाता सूची से बाहर निकालना है।

गृह मंत्री शाह की दो टूक

चुनाव आयोग के एसआईआर में हस्तक्षेप अस्वीकार्य, घुसपैठ पर राजनीति न करें लोग

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान चुनाव आयोग के एसआईआर और घुसपैठ के मुद्दे पर अहम बयान दिए। शाह ने दूसरे देश से आने वाले लोगों की संख्या पर अंकुश लगाने को जरूरी बताते हुए कहा कि अगर बिना किसी पाबंदी के लोगों को आने दिया गया तो देश धर्मशाला बनकर रह जाएगा।

चुनाव आयोग की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं

एक कार्यक्रम में शाह ने कहा, घुसपैठ को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं देने की बात पर भी जोर दिया। अमित शाह ने मतदाता सूची शुद्धिकरण के लिए निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया- विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का जिक्र करते हुए कहा, चुनाव आयोग की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, एसआईआर चुनाव आयोग की सांविधानिक जिम्मेदारी है।

अब पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी

बता दें कि निर्वाचन आयोग ने हाल ही में बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की है। अब आयोग पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तैयारी कर रहा है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कुछ अन्य विपक्षी राजनेताओं ने भी निर्वाचन आयोग के इस फैसले का मुखरता से विरोध किया है।

अशोकनगर, शिवपुरी और बमोरी सहित पूरे गुना संसदीय क्षेत्र में लगे 117 विद्युत उपकेन्द्रः सिंधिया

नई दिल्ली।केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपने अशोकनगर प्रवास के दौरान सेमरा डोंगरा, बिला खेड़ी में दो नए 33/11 के.वी. विद्युत उपकेंद्रों का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के हजारों ग्रामीण परिवारों को स्थायी, गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध विद्युत आपूर्ति का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि इस जिले में उन्होंने कुल 23 नए विद्युत उपकेन्द्र बनवा दिए हैं जिनमें से 15 तो पिछले 15 जिलों में लगे हैं।

सिंधिया ने जनता को संबोधित कहा कि आज का यह अवसर केवल ईंट और पत्थर का नहीं, बल्कि उज्जवल भविष्य की नींव रखने का क्षण है। इन उपकेंद्रों से हमारे किसानों के खेतों में रोशनी फैलेगी, हमारे बच्चों की पढ़ाई बिना रुकावट जारी रहेगी, और हमारे छोटे उद्योगों को निरंतर ऊर्जा प्राप्त होगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके तहत हर घर तक विश्वसनीय और सस्ती बिजली पहुंचाना हमारा संकल्प है।

दलित आईपीएस की मौत पर चिराग पासवान का हरियाणा के सीएम को पत्र, उच्च जाँच की मांग

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की कथित आत्महत्या की उच्चस्तरीय जाँच की माँग की। एक्स पर एक पोस्ट में, लोक जनशक्ति पार्टी के आधिकारिक हैंडल से कहा गया, 'राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक पत्र लिखकर हरियाणा के वरिष्ठ दलित आईपीएस अधिकारी, एडीजीपी वाई. पूरन कुमार की जबरन आत्महत्या की उच्चस्तरीय जाँच का अनुरोध किया है।

आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की मौत से व्यापक आक्रोश फैल गया है और सभी राजनीतिक दलों ने निष्पक्ष जाँच की माँग की है। हरियाणा के

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और इसे एक दुखद क्षति बताया। बेदी ने कहा, 'यह दुखद है। उनकी आत्महत्या से मौत हो गई... पूरा मामला बेहद पेचीदा है... चंडीगढ़ पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जिनकी ज़रूरत है। हरियाणा की इसमें कोई अहम भूमिका नहीं है... वह मेरे समुदाय से थे... ऐसे सफल अधिकारी का जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।'

इस बीच, पंजाब के वित्त मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा ने कथित आत्महत्या की स्वतंत्र न्यायिक जाँच की माँग करते हुए दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार में दलितों पर अत्याचार खतरनाक स्तर पर पहुँच गए हैं। चीमा ने एक्स पर लिखा, 'भाजपा शासन में दलितों पर अत्याचार हर हद पार कर गया है - भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमले से लेकर अब एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने तक। यह उत्पीड़न है। हम एक स्वतंत्र न्यायिक जाँच की माँग करते हैं। भाजपा इस अन्याय की कीमत चुकाएगी।'

मेघालय सीएम संगमा ने मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने का आह्वान किया, राज्यपाल से मिले

मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के अध्यक्ष कॉनराड संगमा ने शुक्रवार को मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने का आह्वान किया। उन्होंने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला सहित विभिन्न हितधारकों से मुलाकात कर चल रहे संघर्ष के बीच स्थायी शांति के सुझावों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री दो दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुँचे और फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन (एफओसीएस) के कार्यवाहक अध्यक्ष बीएम याइमा शाह और मणिपुर इंटीग्रिटी समन्वय समिति (सीओसीओएमआई) के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की।

मुख्यमंत्री संगमा ने इम्फाल, मणिपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैंने कल मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात की। हमने विभिन्न संगठनों से मिले सुझावों पर चर्चा की और बताया कि मणिपुर सरकार और भारत सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए क्या कर सकती है।' संगमा ने आगे कहा कि एनपीपी द्वारा दिए गए सुझावों का भी स्वागत किया गया। COCOMI के प्रवक्ता मायेंगबाम धनंजय ने कहा कि संगठन ने मुख्यमंत्री संगमा से राज्य के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों को खोलने और अवैध अंतर-सीमा नशीली दवाओं के व्यापार और हथियारों के खतरे को रोकने पर विचार करने का अनुरोध किया।

COCOMI के प्रवक्ता ने एएनआई को बताया, 'हमने नशीली दवाओं के व्यापार और अवैध हथियारों के खतरे के साथ-साथ अवैध घुसपैठ की बढ़ती स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा से आग्रह किया। हमने उनसे राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने का आग्रह किया, क्योंकि यह देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। लगभग ढाई साल से हमारे राजमार्ग अवरुद्ध हैं, हम अभी भी वहाँ से नहीं गुजर पा रहे हैं।' मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के बारे में उन्होंने कहा, 'हमने उनसे राजमार्गों को खोलने का आग्रह किया और खतरों को नियंत्रित करने के लिए परामर्श के साथ एक मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो बनाने का भी अनुरोध किया।'

पटाखों की चिंगारी से लगी आग में दो कारें जलकर खाक, कोई हताहत नहीं

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक कॉलोनी में एक पार्क के पास पटाखे की चिंगारी से आग लगने के कारण एक सीएनजी वाहन सहित दो कारें जलकर खाक हो गईं। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकारियों के अनुसार, बच्चे बृहस्पतिवार रात करीब 11 बजे पार्क के पास पटाखे जला रहे थे कि तभी एक जलता हुआ पटाखा पार्किंग क्षेत्र में जा गिरा, जिससे एक पुरानी कार में आग लग गई और आग जल्द ही पास में खड़ी एक अन्य गाड़ी तक फैल गई। उन्होंने बताया कि स्थानीय निवासियों ने पानी से आग बुझाने की कोशिश की लेकिन वे नाकाम रहे। अधिकारियों ने बताया कि घने धुएं और लपटों के उठने से इलाके में दहशत फैल गई। उन्होंने बताया कि दमकलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और लगभग 20 मिनट की मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पा लिया गया।

उदयनिधि स्टालिन का BJP पर बड़ा हमलाः NEP से तमिलनाडु पर थोप रहे संस्कृत-जाति शिक्षा

चेन्नई। तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की युवा शाखा के सचिव उदयनिधि स्टालिन ने शुक्रवार को भाजपा पर नई शिक्षा नीति के ज़रिए संस्कृत और जाति-आधारित शिक्षा थोपने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि तमिलनाडु ऐसे कदमों का विरोध करेगा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा, AIADMK के समर्थन से, राज्य पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है और चेतावनी दी कि अ्श्ख तमिलनाडु में फ़ासीवाद के खिलाफ़ लड़ाई जारी रखेगी और उसे हराएगी।

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने विद्वान वी. आनाइमुथु की शताब्दी पुस्तक विमोचन समारोह में बोलते हुए कहा कि भाजपा नई शिक्षा नीति के ज़रिए संस्कृत और जाति-आधारित शिक्षा थोपने की कोशिश कर रही है, लेकिन तमिलनाडु इसका डटकर विरोध करेगा। भाजपा अपने पुराने गुलाम, अन्नाद्रमुक के समर्थन से किसी भी कीमत पर तमिलनाडु पर कब्ज़ा करने आई है। अब वे नए गुलामों की तलाश में हैं। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ।

तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दो दिन पहले, राज्यपाल ने अपना चुनाव अभियान शुरू किया। वह पूछते हैं कि तमिलनाडु किसके खिलाफ लड़ रहा है। चार साल से, तमिलनाडु उनके खिलाफ लड़ रहा है। हम लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। जब तक आखिरी द्रमुक कार्यकर्ता खड़ा है, राज्य फासीवाद का विरोध करता रहेगा। इससे पहले, बुधवार को उन्होंने भाजपा, अन्नाद्रमुक और तमिलनाडु के राज्यपाल पर हमला बोला और अप्रत्यक्ष रूप से अभिनेता विजय की तमिलगा वेत्री कझगम को राज्य में भाजपा का 'नया गुलाम' बताया।

त्रिची के कलैग्नार अरिवालयम में श्रीरंगम निर्वाचन क्षेत्र के लिए द्रमुक पदाधिकारियों की एक बैठक में बोलते हुए, उदयनिधि ने कहा, 'भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार तमिलनाडु पर कब्ज़ा करने के लिए अन्नाद्रमुक और नए गुलामों के साथ मिलकर साजिश रच रही है।' उन्होंने यह भी कहा कि राज्य पिछले चार सालों से राज्यपाल आर.एन. रवि के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और जीत हासिल होने तक ऐसा करता रहेगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, 'चाहे ऐसी कितनी भी साजिशें क्यों न रची जाएँ, द्रमुक कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य फासीवादी ताकतों से अछूता रहे।'

बिहार चुनाव में चाचा पशुपति पारस ने भरी हुंकार, चिराग की पार्टी के खिलाफ हर सीट पर उतारेंगे उम्मीदवार

पटना। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (आरएलजेपी) प्रमुख पशुपति कुमार पारस उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेंगे जहां उनके भतीजे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (आरवी) 6 और 11 नवंबर को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ेगी। रालोजपा के मुख्य प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने बताया कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने यह निर्णय लिया है कि पार्टी चिराग द्वारा उतारे गए सभी उम्मीदवारों को करारी हार सुनिश्चित करेगी। अग्रवाल ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, रालोजपा उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी जहाँ लोजपा (रालोजपा) चुनाव लड़ेगी। पारस का यह फैसला उनके उस बयान के कुछ ही दिनों बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनके भतीजे चिराग राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होगी।

वर्तमान में विपक्षी महागठबंधन का हिस्सा होने का दावा करते हुए, जिसमें राजद अपने कोटे से रालोसपा को शामिल कर सकता है, पारस ने कहा कि उनकी पार्टी उन्हें आवंटित किसी भी सीट पर चुनाव लड़ेगी। अपने बड़े भाई दिवंगत रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के अवसर पर बुधवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पारस ने कहा, 'लेकिन इसके अलावा, चिराग की लोजपा (रालोद) जहाँ भी उम्मीदवार उतारेगी, मैं वहाँ निर्दलीय उम्मीदवार उतारने पर विचार करूँगा।' आरएलजेपी के एक नेता ने बताया कि यह फैसला पार्टी को इंडिया ब्लॉक में औपचारिक रूप से शामिल करने और सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा में हुई अत्यधिक देरी के कारण लिया गया।

पटाखों पर प्रतिबंध हटाने की एसजी की अनूठी दलील

सीजेआई गवई के भीतर बैठे बच्चे से की अपील

नई दिल्ली। राजाधानी और एनसीआर क्षेत्र में पटाखे चलाने पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को दिवाली के कुछ दिनों तक हटाये जाने की अपील करते हुए सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में एक अनूठी दलील पेश करते हुये प्रधान न्यायाधीश से कहा कि वह अपने भीतर बैठे एक बच्चे के माध्यम से उनके भीतर बैठे बच्चे से इसके लिए अपील कर रहे हैं।

सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय की तरफ से कहा गया कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखे चलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध 'न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श' स्थिति है क्योंकि इस प्रकार के निषेधों का प्रायः उल्लंघन होता है और सभी पक्षों के बीच संतुलन कायम करना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष दिल्ली एवं एनसीआर राज्यों की ओर से दलील देते हुए मेहता ने कहा कि दिवाली तथ अन्य त्योहारों पर बच्चों को समय सीमा के किसी प्रतिबंध के बिना पटाखे चलाने की छूट मिलनी चाहिए।

मेहता ने कहा, ''बच्चों को दो दिन जश्न मनाने दीजिए। यह केवल दिवाली, गुरुपरब, बड़े दिन के लिए है।'' उन्होंने अनुरोध किया, ''मेरे भीतर का बच्चा आपके (न्यायाधीशों) के भीतर बैठे बच्चे को मनाने की कोशिश कर रहा है और कुछ दिनों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।''

प्रतिबंध में छूट देने का संकेत देते हुए प्रधान न्यायाधीश गवई ने कहा कि सभी पक्षों के बीच संतुलन की जरूरत है तथा इस प्रकार के प्रतिबंध 'न तो व्यावहारिक हैं और न ही आदर्श' स्थिति है। पीठ ने दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र में हरित पटाखों के निर्माण और बिक्री के अनुरोध वाली याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।

चुनावी बिगुल से पहले राजद का बड़ा दांव, जदयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा थामेंगे लालटेन

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) को झटका लगा है। पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, जो एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। पूर्णिया से दो बार सांसद रहे कुशवाहा के अलावा बांका से जदयू सांसद गिरधारी यादव के पुत्र चाणक्य प्रकाश रंजन और जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के पुत्र राहुल शर्मा भी राजद में शामिल होने वाले हैं।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि आज एक औपचारिक प्रवेश समारोह होगा, जिसमें राजद के वरिष्ठ नेता एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नए सदस्यों का स्वागत करेंगे। कुशवाहा का दलबदल विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि वे पूर्णिया क्षेत्र में जदयू का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं। राजद में उनके शामिल होने से क्षेत्र में पार्टी के वोट शेयर और संगठनात्मक ताकत पर असर पड़ सकता है, खासकर उन समुदायों के बीच जिन्होंने पिछले कार्यकालों में उनका समर्थन किया था।

इसके अलावा, चाणक्य प्रकाश और राहुल शर्मा अपने राजनीतिक वंश के कारण महत्वपूर्ण सदस्य हैं। राहुल शर्मा पहले विधायक रह चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस कदम को राजद द्वारा अनुभवी नेताओं और प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में स्थापित स्थानीय प्रभाव वाले नेताओं को शामिल करके अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के एक रणनीतिक प्रयास के रूप में देखते हैं।

अचानक इलेक्शन कमीशन का बचाव कर रहे संजय राउत! बोले- 'कभी सुनना भी चाहिए'

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

चुनाव आयोग पर आए दिनों आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने आयोग के पक्ष में बयान देकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. राउत ने कहा कि अगर चुनाव आयोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुछ नियम बनाता है तो उसे सुनना भी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि हर बार आयोग की आलोचना करना उचित नहीं है, क्योंकि यह संस्था लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है.

सुप्रीम कोर्ट में चली गर्मागर्म बहस

सुप्रीम कोर्ट में विशेष गहन पुनरीक्षण मामले की सुनवाई के दौरान भारतीय चुनाव आयोग ने गंभीर आरोप लगाए. आयोग ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल और एजेंसियां चुनाव आयोग के प्रयासों में सहयोग करने के बजाय जनता की धारणा को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं. आयोग ने साफ शब्दों में कहा कि कुछ दल चुनाव प्रक्रिया को लेकर 'नैरेटिव सेट' करना चाहते हैं, जिससे निष्पक्ष चुनावी माहौल

पर असर पड़ता है.

संजय राउत ने दिया संतुलित बयान

संजय राउत ने कहा, 'ठीक है, चुनाव आयोग को सुनना भी चाहिए. अगर किसी बात से लोकतंत्र को खतरा है तो आयोग का नियम बनाना गलत नहीं. हर बार चुनाव आयोग की आलोचना करना ठीक नहीं.' उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में आयोग के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है. राउत का यह रुख विपक्ष के कुछ नेताओं से अलग है, जो पिछले दिनों चुनाव आयोग की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे थे.

पहले लगाया था बड़ा आरोप

हालांकि इससे पहले खुद संजय राउत ने ही चुनाव आयोग पर निशाना साधा था. बिहार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद उन्होंने कहा था, 'बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा आयोजित करके, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने निष्पक्ष चुनाव कराने के अपने दृष्टिकोण के लिए भारत के चुनाव आयोग और भाजपा की पोल खोल दी है.' उनके इस पुराने बयान और अब दिए गए समर्थन के बीच बड़ा विरोधाभास दिख रहा है. यही वजह है कि अब राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि राउत का रुख क्यों बदला और क्या यह आने वाले चुनावी समीकरणों से जुड़ा हुआ है.

कुछ लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, उन्हें समझाया जाए सच्चा हिंदुत्व और देशभक्तिः उद्धव

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि कुछ लोगों ने "अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है" और उन्हें यह समझाना ज़रूरी है कि सच्चा हिंदुत्व और देशभक्ति क्या होती है। वह यहां उपनगरीय बांद्रा स्थित अपने घर मातोश्री के बाहर कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। ठाकरे ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर के स्वागत में लगाए गए बैनरों पर उनकी तस्वीर को लेकर कटाक्ष किया और कहा कि मंत्री अपने प्रचार के प्रति जुनूनी हैं। शिंदे शिवसेना के प्रमुख हैं। ठाकरे ने कहा, क्या आप (शिंदे) उनके (स्टार्मर) क़रीब भी पहुंच पाए? वे आत्म-प्रचार में मुग्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर परोक्ष हमला

करते हुए उन्होंने कहा, सच्ची देशभक्ति और हिंदुत्व को समझाना ज़रूरी है। कुछ लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित किसान हताश हैं और सरकार ने उनके लिए छल का पैकेज घोषित किया है। ठाकरे हाल में भारी बारिश और बाढ़ के कारण फसलें गंवाने वाले किसानों के लिए घोषित वित्तीय सहायता का ज़िक्र कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे शनिवार को छत्रपति संभाजीनगर में किसानों के लिए 'अपर्याप्त' वित्तीय पैकेज के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेंगे।

'मराठा समाज को ओबीसी में शामिल किया होता, तो आज...', आरक्षण विवाद पर विखे पाटिल का शरद पवार पर तंज

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र भर में सियासी गर्माहट तेज हो गई है। इसी बीच राज्य के मंत्री और राज्य मंत्रिमंडल की मराठा आरक्षण पर बनी उप-समिति के प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटिल ने एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 1994 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय पवार ने अगर मराठा समुदाय को ओबीसी में शामिल किया होता, तो आज यह आरक्षण विवाद खड़ा ही नहीं होता।

ये बात मंत्री पाटिल ने जलगांव के अंतरवाली सराटी गांव में मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जरांगे से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा। इस दौरान विखे पाटिल ने कहा कि यह एक निजी भेंट थी। मैं सिर्फ उनकी तबीयत जानने आया था। हमने कुछ सामान्य मुद्दों पर चर्चा की। शरद पवार को लेकर क्या बोले विखे पाटिल?

विखे पाटिल ने आगे कहा कि शरद पवार को अब सामने आकर अपने रुख को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने मराठाओं को ओबीसी में शामिल न करके सामाजिक असमानता की नींव रखी। आज की स्थिति के लिए वही जिम्मेदार हैं। उन्होंने ओबीसी नेताओं से अपील की कि वे मराठा आरक्षण का विरोध न करें, क्योंकि हाईकोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मंत्री छगन भुजबळ से भी आरक्षण का विरोध न करने की अपील की।

विखे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार के आदेश का किया जिक्र

इस दौरान विखे पाटिल ने कहा कि दो सितंबर को सरकार द्वारा जारी किया गया जीआर (सरकारी आदेश), जिसमें मराठा समुदाय के उन सदस्यों को कुंभी जाति प्रमाणपत्र देने की बात है जो अपने ओबीसी मूल को साबित कर सकते हैं, फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सभी को कोर्ट का निर्णय स्वीकार करना चाहिए।

मध्य रेल के सोलापुर मंडल में 55वीं डीआरयूसीसी बैठक में यात्री-केंद्रित विकास पर चर्चा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल के सोलापुर मंडल की मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति (डीआरयूसीसी) की 55वीं बैठक 10 अक्टूबर 2025 को सोलापुर स्थित डीआरएम कार्यालय के संगम सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सोलापुर के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) डॉ. सुजीत मिश्रा ने की और इसमें सांसदों तथा सोलापुर, कलबुरगि, लातूर, कुर्डुवाडी, पंढरपुर और जेउर के विभिन्न यात्री एवं व्यापारिक संगठनों के सदस्यों के 12 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

यह बैठक भारतीय रेल की सहभागी शासन और निरंतर सेवा सुधार के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप, रेल प्रशासन और रेल उपयोगकर्ताओं के बीच सार्थक परामर्श और विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है। सत्र के दौरान, डीआरएम सोलापुर ने समिति के सदस्यों को सोलापुर मंडल द्वारा की गई विभिन्न पहलों और यात्री-केंद्रित विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने निम्नलिखित बातों पर प्रकाश डालाः

पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी के लिए किए गए सफल प्रबंध, जिससे तीर्थयात्रियों की सुगम आवाजाही और यात्री सुविधा सुनिश्चित हुई।

आगामी कार्तिकी एकादशी के लिए यात्री यातायात में अपेक्षित वृद्धि को कुशलतापूर्वक संभालने हेतु तैयारियाँ जोरों पर हैं।

हाल ही में आई बाढ़ के दौरान रेल परिचालन का कुशल संचालन, संरक्षा सुनिश्चित करना और सेवाओं में न्यूनतम व्यवधान।

पूरे मंडल में यात्री सुविधाओं, परिचालन दक्षता और सुगमता को बढ़ाने पर केंद्रित बुनियादी ढाँचे का उन्नयन जारी है।

सभी यात्रियों के लिए समावेशिता और यात्रा में आसानी सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न स्टेशनों पर दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाओं की शुरुआत।

त्योहारों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन।

डीआरयूसीसी के सदस्यों ने यात्री सुविधाओं, परिचालन दक्षता और ग्राहक संतुष्टि में सुधार के लिए सोलापुर मंडल द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने यात्री सुविधा और सेवा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए बहुमूल्य सुझाव और प्रतिक्रिया भी साझा किये।

मंडल स्तर पर एक परामर्शदात्री निकाय, डीआरयूसीसी, रेल प्रशासन और विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाले रेल उपयोगकर्ताओं के बीच नियमित संवाद के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि उपयोगकर्ताओं की चिंताओं और सुझावों को सुना जाए, जिससे सेवा सुधार और यात्री संतुष्टि के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले।

अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक (एडीआरएम) अंशुमाली कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) योगेश पाटिल, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक (सीनियर डीओएम) ब्रजेश राय, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समन्वय) सचिन गनेर, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (सामान्य) अभिषेक चौधरी, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (सीनियर डीएमई) रामलाल प्यासे, सहायक वाणिज्य प्रबंधक (एसीएम) सुदर्शन देशपांडे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक के दौरान उपस्थित थे।

बैठक का समापन आपसी विश्वास के साथ हुआ और सोलापुर मंडल में रेल सेवाओं और यात्री अनुभव को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।

छठ पूजा / दिवाली पर्व 2025 के लिए मुंबई और वाराणसी के बीच 12 अतिरिक्त विशेष गाड़ियाँ चलाने का रेलवे का निर्णय

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

आगामी छठ पूजा / दीपावली त्यौहार के अवसर पर यात्रियों की सुविधा हेतु रेलवे द्वारा लोकमान्य तिलक टर्मिनस और वाराणसी के बीच 12 अतिरिक्त विशेष गाड़ियाँ चलाई जाएँगी।

जिनका विवरण इस प्रकार हैः

एलटीटी-वाराणसी विशेष गाड़ियाँ

04225 विशेष गाड़ी लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मुंबई से प्रत्येक मंगलवार को 14.10.2025 से 18.11.2025 तक सायं 16.55 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन प्रातः 02.05 बजे वाराणसी पहुँचेगी।

04226 विशेष गाड़ी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार को 13.10.2025 से 17.11.2025 तक रात्रि 01.35 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन दोपहर 14.25 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मुंबई पहुँचेगी।

ठहरावः ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, रानी कमलापति (भोपाल), बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, उरई, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर सिटी।

संरचनाः 4 एसी-2 टियर, 9 एसी-3 टियर तथा 2 जनरेटर कोच।

आरक्षणः विशेष गाड़ी संख्या 04225 के लिए आरक्षण 12.10.2025 से सभी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों एवं वेबसाइट www.irctc.co.in पर शुरू होगी।

विशेष गाड़ियों के ठहरावों की विस्तृत समय सारिणी हेतु www.enquiry.indianrail.gov.in वेबसाइट देखें या एनटीईएस ऐप डाउनलोड करें।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे इन विशेष गाड़ियों की सेवाओं का लाभ उठाएँ।

रविवार को मध्य रेल की हार्बर लाइन पर मेगा ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता) । मध्य रेल मुंबई मंडल, रविवार दिनांक 12.10.2025 को विभिन्न इंजीनियरिंग और अनुरक्षण कार्यों के लिए कुर्ला और वाशी स्टेशनों के बीच अप और डाउन हार्बर लाइन पर मेगा ब्लॉक संचालित करेगा।

जिनका विवरण इस प्रकार है - अप और डाउन हार्बर लाइनः कुर्ला और वाशी स्टेशनों के बीच 11.10 बजे से 16.10 बजे तक मेगा ब्लॉक रहेगा। इस बीच निम्न सेवाएँ रद्द रहेंगी : सीएसएमटी मुंबई से वाशी / बेलापुर / पनवेल की ओर जाने वाली डाउन हार्बर लाइन की लोकल सेवाएँ, जो 10.34 बजे से 15.36 बजे के बीच प्रस्थान करती हैं, रद्द रहेंगी। पनवेल / बेलापुर / वाशी से सीएसएमटी मुंबई की ओर आने वाली अप हार्बर लाइन की लोकल सेवाएँ, जो 10.17 बजे से 15.47 बजे के बीच प्रस्थान करती हैं, रद्द रहेंगी। विशेष उपनगरीय गाड़ियाँ - ब्लॉक अवधि के दौरान सीएसएमटी मुंबई - कुर्ला तथा पनवेल - वाशी खंडों के बीच विशेष उपनगरीय गाड़ियाँ चलाई जाएँगी। ब्लॉक अवधि में यात्रियों को ठाणे - वाशी / नेरुल स्टेशनों के बीच 10.00 बजे से 18.00 बजे तक यात्रा करने की अनुमति होगी। सीएसएमटी और कल्याण के बीच मुख्य लाइन पर कोई मेगा ब्लॉक नहीं रहेगा ये अनुरक्षण मेगा ब्लॉक रेल संरचना के रख-रखाव और सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि होने वाली असुविधा के लिए रेलवे प्रशासन का सहयोग करें।

पश्चिम रेलवे का रविवार को बोरीवली - राम मंदिर तथा राम मंदिर - कांदिवली स्टेशनों के बीच जम्बो ब्लॉक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

रेलपथ, सिगनलिंग प्रणाली एवं ऊपरी उपस्करों के रख-रखाव कार्य हेतु पश्चिम रेलवे द्वारा रविवार, 12 अक्टूबर, 2025 को 10.00 बजे से 14.00 बजे तक बोरीवली - राम मंदिर स्टेशनों के बीच अप फास्ट लाइनों पर तथा राम मंदिर - कांदिवली स्टेशनों के बीच 5वीं लाइन पर चार घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान सभी अप फास्ट लाइन की ट्रेनें बोरीवली एवं अंधेरी स्टेशनों के बीच अप स्लो / 6वीं लाइन पर चलाई जाएंगी। इसी प्रकार, 5वीं लाइन की सभी ट्रेनों को अंधेरी एवं बोरीवली स्टेशनों के बीच डाउन फास्ट लाइन पर चलाया जायेगा।

ब्लॉक के कारण कुछ उपनगरीय ट्रेनें

निरस्त रहेंगी तथा कुछ अंधेरी एवं बोरीवली ट्रेनों को गोरेगांव तक हार्बर लाइन पर चलाया जाएगा।

इस ब्लॉक से संबंधित विस्तृत जानकारी संबंधित स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व उपरोक्त व्यवस्था को ध्यान में रखें।

मध्य रेल

16 स्थानों पर उद्घोषक सह संकेतक ऑपरेटरों की आउटसोर्सिंग

मुंबई मंडल के 16 स्थानों पर उद्घोषणा और संकेतक प्रणाली को चौबीसों घंटे संचालित करने के लिए उद्घोषक–सह–संकेतक प्रचालकों की आउटसोर्सिंग + एक पर्यवेक्षक दो साल (730 दिन) की अवधि के लिए **www.gem.gov.in** पर ई– टेंडरिंग मॉड्यूल के माध्यम से निविदा आमंत्रित की है। इच्छुक बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है और सभी आवश्यक दस्तावेज बोली खुलने से पहले अपलोड करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे विवरण जानने के लिए वेबसाइट **www.gem.gov.in** पर जाएं। **खुला निविदा–GeM संख्याः** GEM/2025/B/6761288 दिनांक 07.10.2025 **कार्य का नामः** मुंबई मंडल के 16 स्थानों पर उद्घोषणा और संकेतक प्रणाली को चौबीसों घंटे संचालित करने के लिए उद्घोषक–सह–संकेतक प्रचालकों की आउटसोर्सिंग + एक पर्यवेक्षक दो साल (730 दिन) की अवधि के लिए **कार्यालय का पताः** वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय, वाणिज्य शाखा, मुंबई मंडल **कार्यस्थलः** मुंबई मंडल के 16 स्थान **विज्ञापित मूल्यः** Rs. 4,23,05,951.24/– **निविदा का प्रकारः** दो पैकेट प्रणाली **निविदा बंद होने की तारीख और समयः** 28–10–2025 at 17:00 Hrs **कार्यकालः** दो वर्ष (730 दिन) **प्रस्तावों की वैधताः** 60 दिन (जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है) **वेबसाइट पर निविदा दस्तावेज उपलब्ध हैः** **https://gem.gov.in/** विषय निविदा के संबंध में आगे कोई शुद्धिपत्र/संशोधन, निविदा वापस लेना, तारीख में बदलाव, समय विस्तार, स्पष्टीकरण आदि, यदि कोई हो, केवल वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। बोलीदाताओं को स्वयं को अद्यतन रखने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट पर जाना चाहिए। 533

टिकट के लिए UTS APP डाउनलोड करे

ऐरोली थिएटर के स्थल निरीक्षण के बाद कार्य की गति के संबंध में आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे के निर्देश

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नवी मुंबई नगर निगम की ओर से ऐरोली सेक्टर 5 स्थित प्लॉट संख्या 37 पर बन रहे नूतन नाट्यगृह के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद, नगर आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे ने नए साल की शुरुआत तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर आयुक्त के साथ नगर अभियंता श्री शिरीष आर्डवाड, अतिरिक्त नगर अभियंता श्री अरविंद शिंदे, कार्यपालक अभियंता श्री संजय पाटिल और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

नवी मुंबई नगर निगम का वाशी में एक विष्णुदास भावे थिएटर है और कला एवं संस्कृति प्रेमियों की अच्छी प्रतिक्रिया को देखते हुए, ऐरोली में एक नए थिएटर के निर्माण का कार्य चल रहा है।

860 सीटों वाला यह थिएटर चार मंजिला है और इसके पहले और दूसरे बेसमेंट में चार पहिया और दो पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ, भूतल का एक हिस्सा पार्किंग के लिए है, और मुख्य प्रवेश द्वार पर एक स्वागत कक्ष, टिकट बुकिंग कार्यालय, भोजन काउंटर, प्रशासनिक हॉल, भंडार कक्ष और नाट्य सामग्री के संचालन के लिए एक अलग प्रवेश द्वार है।

पहली मंजिल पर 478 सीटों वाला एक मंच और सभागार, एक ध्वनि नियंत्रण कक्ष और एक रंग अभ्यास कक्ष है।

दूसरी मंजिल पर 382 लोगों की बैठने की क्षमता वाला एक बहुउद्देश्यीय हॉल, एक भंडारण कक्ष और महिला कलाकारों के लिए एक पोशाक कक्ष है।

तीसरी मंजिल पर पुरुषों का ड्रेसिंग रूम और ध्वनि/प्रकाश नियंत्रण कक्ष है।

चौथी मंजिल पर एक विशेष अतिथि कक्ष और कलाकारों की सुविधाओं के लिए एक कक्ष है।

इस थिएटर में छह यात्री लिफ्ट और एक हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रणाली है।

पूरे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद, आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे ने यहाँ कार्य की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की। भौतिक निरीक्षण के बाद, आयुक्त ने वास्तुकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना का प्रस्तुतीकरण देखने के बाद मूलभूत सुझाव दिए। वर्तमान में इस परियोजना का लगभग 65 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे ने निर्देश दिया कि इस काम की गुणवत्ता बनाए रखते हुए काम में तेजी लाई जाए और नए साल की शुरुआत तक काम पूरा करने के लिए समयबद्ध योजना बनाई जाए।

पश्चिम रेलवे द्वारा त्योहारी सीज़न 2025 के दौरान व्यापक भीड़ प्रबंधन व्यवस्था

यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र सुरक्षित और व्यवस्थित त्योहारी यात्रा सुनिश्चित करने हेतु पश्चिम रेलवे की सक्रिय तैयारी

त्योहारी सीज़न के दौरान यात्रियों के सुरक्षित और व्यवस्थित बोर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए समर्पित होल्डिंग एरिया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

आगामी त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ और यात्रियों की आवाजाही में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा सुरक्षित, सुचारू और कुशल रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक भीड़ प्रबंधन और यात्री सुविधा उपाय शुरू किए गए हैं। मुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस, बोरीवली, वापी, वलसाड, उधना और सूरत सहित प्रमुख स्टेशनों पर विशेष व्यवस्थाएँ की गई हैं।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सभी निर्दिष्ट यात्री आवास क्षेत्रों में बैठने की व्यवस्था, पेयजल सुविधा, शौचालय, पर्याप्त रोशनी, पंखे और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली जैसी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। यात्रियों के प्रवेश और टिकटिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक स्थान पर अतिरिक्त काउंटर स्थापित किए गए हैं, साथ ही कतार नियमन, सहायता और सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्टेशन पर लगभग 20 अतिरिक्त टिकट चेकिंग स्टाफ और आरपीएफ कर्मियों की तैनाती भी की गई है।

श्री विनीत ने आगे बताया कि ट्रेन प्रस्थान से पहले प्रतीक्षारत यात्रियों को आराम से समायोजित करने के लिए सभी प्रमुख स्टेशनों पर पर्याप्त कवर्ड होल्डिंग क्षमता बनाई गई है। बांद्रा टर्मिनस पर, प्लेटफ़ॉर्म संख्या 1 के पूर्व की ओर प्रवेश द्वार के पास 210 वर्ग मीटर से अधिक का आश्रय क्षेत्र उपलब्ध कराया गया है, जबकि वापी में, यात्रियों के एकत्र होने के लिए एफओबी लैंडिंग के पास 110 वर्ग मीटर से अधिक का कवर्ड क्षेत्र तैयार किया गया है। उधना स्टेशन को पूरे मंडल में सबसे बड़ी होल्डिंग क्षमता प्रदान की गई है, जिसमें स्टेशन के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर 3200 वर्ग मीटर से अधिक के तीन चिह्नित कवर्ड स्थान हैं, जिनमें से एक क्षेत्र वर्तमान में होल्डिंग क्षमता को और बढ़ाने के लिए निर्माणाधीन है। इसी प्रकार, सूरत में, 1,200 वर्ग मीटर से अधिक के दो निर्दिष्ट होल्डिंग क्षेत्र तैयार किए गए हैं, एक पीआरएस कार्यालय से सटे पश्चिमी प्रवेश द्वार के पास और दूसरा बुकिंग कार्यालय के पास पूर्व की ओर जिससे त्योहारों के समय होने वाली भीड़ के दौरान व्यवस्थित रूप से यात्रियों को लाने और नियमित रूप से चढ़ने में मदद मिलेगी। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों से अपील की गई है कि वे प्लेटफॉर्म या प्रवेश द्वारों के पास भीड़ लगाने के बजाय निर्धारित प्रतीक्षालयों का उपयोग करें, ताकि व्यस्त समय के दौरान आवाजाही सुचारू रूप से नियंत्रित की जा सके। यात्रियों से ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों के दिशानिर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया गया है, क्योंकि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य सभी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देना है। त्योहारों की भीड़ के दौरान कम समय में हजारों यात्रियों के ट्रेनों में चढ़ने की उम्मीद के साथ व्यवस्था बनाए रखने और समय पर प्रस्थान सुनिश्चित करने में सामूहिक सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नागपुर में बनेगा विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

स्पेन की फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई।नागपुर में सभी सुविधाओं से युक्त एक विश्वस्तरीय 'कन्वेंशन सेंटर' स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में वर्षा के आवास पर स्पेन की फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुझाव दिया कि नागपुर में स्थापित होने वाले 'कन्वेंशन सेंटर' के लिए चयनित स्थान सभी परिवहन सेवाओं से अच्छी तरह जुड़ा होना चाहिए।

इस अवसर पर भारत में स्पेन के राजदूत जुआन एंटोनियो, फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ रिकार्डो ज़ापाटेरो, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, पायनियर एक्जीबिशन एंड कन्वेंशन प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अरोड़ा और उपाध्यक्ष जीत अरोड़ा, नागपुर के जिला कलेक्टर विपिन इटनकर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि नागपुर में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति 'कन्वेंशन सेंटर' के माध्यम से नागपुर के इतिहास को जान सके। यह सेंटर अत्यंत

का उपयोग केवल प्रदर्शनियों, कार्यक्रमों आदि के लिए ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी एक उचित मंच होना चाहिए। कन्वेंशन सेंटर की आंतरिक संरचना आकर्षक, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित और पर्यावरण-अनुकूल वास्तुकला का एक अनुकरणीय उदाहरण होना चाहिए।

स्पेनिश राजदूत ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ के बीच अच्छे संबंध हैं। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मज़बूत हो रहे हैं। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक की मदद से आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है और दुनिया ने इस पर ध्यान दिया है। मुंबई न केवल भारत का, बल्कि दक्षिण एशिया का भी एक 'पावरहाउस' बन रहा है। इसलिए, स्पेन निश्चित रूप से महाराष्ट्र के साथ काम करना चाहेगा, जिसकी राजधानी मुंबई है, उन्होंने इन शब्दों में महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाया।

फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल कंपनी की ओर से सीईओ रिकार्डो ज़ापाटेरो ने एक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नागपुर और फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुइके के निर्देश

टीआरटीआई को आदिवासी समुदायों पर शोध पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। आदिवासी समुदाय के रीति-रिवाजों, बोली-भाषा, रहन-सहन और आय के स्रोतों पर व्यापक शोध की आवश्यकता है। इस शोध के आधार पर समाज के अंतिम तबके के कल्याण हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इसलिए, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुइके ने निर्देश दिया कि आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (टीआरटीआई) को आदिवासी समुदाय पर शोध पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि 'टीआरटीआई' के सशक्तिकरण के लिए संबंधित संवर्गों के अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। अनुसंधान शाखा को सुदृढ़ बनाने के लिए मानवशास्त्रियों और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए। महापुरुषों पर आधारित पुस्तकें प्रकाशित की जाएँ ताकि अंतिम समुदाय के छात्र आदिवासी समुदाय के महापुरुषों के इतिहास को जान सकें। आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संबंध में मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभाग के सचिव विजय वाघमारे, 'टीआरटीआई' की आयुक्त दीपा मुधोल-मुंडे, संयुक्त सचिव श्री शेल्के, संस्थान की संयुक्त निदेशक चंचल पाटिल, उपनिदेशक श्री फिरके, प्रशासनिक

अधिकारी कैलास खेडकर आदि उपस्थित थे।

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुइके ने कहा कि आदिवासी विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आदिवासी समुदाय पर शोध पर आधारित विभिन्न प्रकाशन नियमित रूप से तीन या छह महीने के अंतराल पर प्रकाशित किए जाने चाहिए। 'टीआरटीआई' के अंतर्गत आदिवासी प्रकोष्ठ में आदिवासी समुदाय की सभी जातियों को शामिल करके इन जातियों पर शोध किया जाना चाहिए।

अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समितियों को मजबूत किया जाना चाहिए। समितियों में वकीलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। लंबित शैक्षणिक मामलों के पुराने मामलों का अभियान चलाकर समाधान किया जाना चाहिए। आदिवासी समुदाय के छात्रावासों के वार्डनों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजाति वर्ग के पीएचडी छात्रों को नियमित रूप से फेलोशिप दी जानी चाहिए। आदिवासी समाज के लिए काम करने वाले सभी महापुरुषों की जयंती और शहीद दिवस की जानकारी संकलित की जानी चाहिए। आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से इन महापुरुषों की जयंती मनाई जानी चाहिए, ऐसा आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुइके ने कहा।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जयंती पर 'वाचन प्रेरणा दिवस' मनाने के सरकारी निर्देश

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने और मराठी भाषा के प्रचार, प्रसार, विकास, संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से, पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जयंती, यानी 15 अक्टूबर को, सरकार ने इसे 'वाचन प्रेरणा दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 'इसे एक भाषा के रूप में लें, आइए मराठी को ज्ञान की भाषा बनाएँ' इस वर्ष की पहल का मुख्य उद्देश्य है।

राज्य सरकार के सभी मंत्रालयिक विभागों के साथ-साथ उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी/अर्ध-सरकारी कार्यालय, सरकारी संस्थान/बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रम, सभी आयुक्त और सभी जिला कलेक्टर कार्यालय 'वचन प्रेरणा दिवस' मनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेंगे। इसमें ऑनलाइन के साथ-साथ व्यक्तिगत कार्यक्रम भी शामिल होंगे। वाचन प्रेरणा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम केवल ललित साहित्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कंप्यूटर, अंतरिक्ष विज्ञान विषयों को भी कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा और अधिकतम युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए रोजगारोन्मुखी गतिविधियाँ क्रियान्वित की जाएँगी। इसमें अनुवाद लेखन, व्यावसायिक लेखन, ई-पुस्तक, स्व-प्रकाशन, ऑनलाइन पुस्तक विक्रय, कोड लेखन, लघु फिल्म/वृत्तचित्र लेखन जैसे विषयों पर कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँगी। इसके साथ ही व्याख्यान, संगोष्ठियाँ, वाचन, समूह वाचन, पुस्तक प्रदर्शनी, 'मराठी वचन कत्त' का निर्माण, मराठी आभासी/भौतिक साहित्यिक सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। मराठी भाषा के प्रयोग को अधिकतम करने के उद्देश्य से, न्यायिक कार्यों, सरकारी प्रशासन, मीडिया आदि में मराठी भाषा के प्रयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। इन कार्यक्रमों के आयोजन हेतु महाराष्ट्र साहित्य परिषद, मराठवाड़ा साहित्य परिषद, विदर्भ साहित्य संघ, कोंकण मराठी साहित्य परिषद, दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा और मुंबई मराठी साहित्य संघ जैसी साहित्यिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। पुस्तकालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी महाविद्यालयों और डिप्लोमा संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संबंधित संगठन भी पठन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसके साथ ही, नगर निगमों/नगर पालिकाओं के अंतर्गत आने वाले संगठन भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे, मराठी भाषा विभाग की सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी ने बताया।

स्कूलों में मराठी भाषाः राष्ट्रगान का गायन अनिवार्य- स्कूली शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे

सभी शिक्षा बोर्डों के समन्वयकों और प्राचार्यों की परामर्श बैठक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई।स्कूली शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने सुझाव दिया है कि राज्य शिक्षा बोर्ड सहित सभी बोर्डों के स्कूलों में मराठी भाषा का अध्ययन-अध्यापन अनिवार्य किया जाना चाहिए और राज्यगान का गायन भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। राज्य के सभी शिक्षा बोर्डों के समन्वयकों, प्राचार्यों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक परामर्श बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई थी। इस अवसर पर स्कूली शिक्षा मंत्री भुसे बोल रहे थे। इस अवसर पर स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल, शिक्षा आयुक्त सच्चचंद्र प्रताप सिंह, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक राहुल रेखावर, स्कूली शिक्षा विभाग के उप सचिव तुषार महाजन, मुंबई संभागीय शिक्षा उपनिदेशक राजेश कंकल सहित

सीबीएसई, आईसीएसई, अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के विभिन्न समन्वयक और स्कूलों के प्राचार्य उपस्थित थे।

स्कूल शिक्षा मंत्री भुसे ने कहा कि आईसीएसई, सीबीएसई और कैम्ब्रिज बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के विद्यार्थियों की दसवीं कक्षा की अंकतालिकाओं में मराठी भी शामिल की जानी चाहिए। इसके लिए विभिन्न बोर्ड के साथ पत्राचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य बोर्ड की तरह आईसीएसई बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और कार्यों से संबंधित पाठ्यक्रम शामिल किया जाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड को मानविकी विषयों में महाराष्ट्र का इतिहास पढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए। दिव्यांग और कम सीखने की क्षमता वाले विद्यार्थियों को भी समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अन्य बोर्ड के स्कूलों में दिए जाने वाले प्रवेश और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लागू की गई विभिन्न पहलों को अन्य बोर्ड के स्कूलों में भी सख्ती और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रथम की भावना का संचार किया जाना चाहिए। 'एक पेड़ माँ के नाम' पहल को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। अच्छी सुविधाओं वाले अन्य बोर्ड के स्कूलों को भी मराठी माध्यम के स्कूलों का मार्गदर्शन करना चाहिए, मंत्री दादाजी भुसे ने भी इस अवसर पर निर्देश दिए।

विभिन्न बोर्डों के समन्वयकों एवं प्रधानाचार्यों ने अपने विद्यालयों में चल रही विभिन्न गतिविधियों, सीखने-सिखाने के प्रयोगों तथा मूल्यांकन विधियों के बारे में जानकारी दी।

मध्य रेल सतर्कता दल ने नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध की कड़ी कार्रवाई

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेल की सतर्कता शाखा ने अवैध टिकटिंग गतिविधियों जैसे कि टिकटों के हस्तांतरण, दलाली गतिविधियाँ, फर्जी पहचान पत्रों व नकली टिकटों पर यात्रा आदि पर लगातार निगरानी रखी है। जनवरी 2025 से मई 2025 तक मध्य रेलवे ट्रैफिक सतर्कता टीम ने ऐसी अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न स्थानों पर आठ निवारक जांचें कीं।

इन जांचों का विवरण इस प्रकार है -

फरवरी 2025 में -

अंबरनाथ (03.02.2025): सॉफ्टवेयर के माध्यम से अवैध ई-टिकटिंग का पता चला . ?12,000 मूल्य के 08 टिकट और 13 आईआरसीटीसी आईडी जब्त किए गए, एफआईआर दर्ज की गई और मामला सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार बंद किया गया।

कोल्हापुर (18.02.2025): चार दलालों को ?25,557 मूल्य के 04 टिकटों के साथ पकड़ा गया। तदनुसार उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

मार्च 2025 में -

पुणे (04.03.2025): डेक्कन जिमखाना पीआरएस पर तीन दलाल ?10,520 मूल्य के 03 जेसीआर टिकटों के साथ पकड़े गए। उन्हें कानूनी कार्रवाई हेतु आरपीएफ को सौंपा गया।

सिस्टम का दुरुपयोग (24.03.2025): एक आरक्षण लिपिक ने व्यक्तिगत लाभ के लिए बिना प्रिंट किए सिस्टम में टिकट जारी किए। उसके विरुद्ध बड़ी शास्ति आरोपित की गई ।

अप्रैल 2025 में-

दो यात्रियों को ट्रेन संख्या 11055 में फर्जी पहचान पत्रों और स्थानांतरित टिकटों के साथ यात्रा करते हुए पकड़ा गया। दोनों पर रेलवे नियमों के अनुसार जुर्माना लगाया गया।

मई 2025 में-

ट्रेन संख्या 12741 में दो गैर-रेलवे कर्मचारी पीआरएस टिकटों पर यात्रा करते हुए पकड़े गए, जो प्रिविलेज पास का उपयोग करके बुक किए गए थे। दोनों पर ?10,990 का जुर्माना लगाया गया। आगे की जांच जारी है।

मलकापुर (22.05.2025): बड़े पैमाने पर दलाली रैकेट का भंडाफोड़; दो व्यक्तियों को ?10.09 लाख मूल्य के 182 जेसीआर टिकटों के साथ पकड़ा गया। दलालों, आरक्षण लिपिक और आईपीएफ के बीच अनाधिकृत संबंधों का पता चला। तदनुसार बड़ी एवं छोटी शास्तियां आरोपित की गईं हैं .

मध्य रेलवे का सतर्कता विभाग रेलवे टिकटिंग संचालन में पारदर्शिता, निष्ठा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वास्तविक यात्रियों के हित में दलाली और अवैध टिकटिंग गतिविधियों को समाप्त करने हेतु निरंतर जांचें और कठोर कार्रवाई की जा रही हैं।

एनएमएमपी के स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

रविवार को नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र में एक उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 0 से 5 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पोलियो का टीका लगाया जाएगा और नगर निगम आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे के मार्गदर्शन में, स्वास्थ्य विभाग ने पोलियो टीकाकरण के लिए उचित योजना बनाई है।

भारत पोलियो मुक्त है। हालाँकि, चूँकि पोलियो अभी भी कुछ देशों में मौजूद है, इसलिए इसे वापस आने से रोकने के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र में 0 से 100 मामले होने की उम्मीद है। 5 वर्ष आयु वर्ग में 88748 बच्चों को टीका लगाने के उद्देश्य से इस अभियान की योजना बनाई गई है। इसके लिए, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के क्षेत्र में 26,618 स्थायी, 76 ट्रांजिट और 27 मोबाइल बूथ। कुल 721 बूथ कार्यरत रहेंगे। इस टीकाकरण अभियान के लिए मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे व्यस्त स्थानों पर ट्रांजिट और मोबाइल टीमें लगाई गई हैं।

इसी प्रकार, नगर निगम के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत जावड़े की अध्यक्षता में सिटी टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई और योजना की समीक्षा की गई। साथ ही, पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु चिकित्सा अधिकारियों, एनएम, एलएचवी, एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस अभियान के लिए जन जागरूकता हेतु नगर निगम क्षेत्र में पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। इस पोलियो टीकाकरण अभियान के अंतर्गत, जिन बच्चों को 12 अक्टूबर, 2025 तक पोलियो की खुराक नहीं मिली है, उन्हें अगले 5 दिनों तक नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से 902 टीमों द्वारा गृह भ्रमण के माध्यम से टीका लगाया जाएगा। पूरे दिन घर-घर जाकर खुराकें वितरित की जाएंगी। इसके लिए प्रत्येक टीम के कार्यक्षेत्र की विस्तृत योजना बनाई गई है।

हालांकि, माता-पिता पोलियो को हराने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान में भाग लेते हैं और अपने 0 से 5 तक के बच्चों को पल्स पोलियो टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। नगर आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे एक वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक बच्चे से पल्स पोलियो टीकाकरण करवाने की अपील कर रहे हैं।

संविधान जागरूकता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए बार्टी और टीआरटीआई धन उपलब्ध कराएँ- राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। राज्य के विद्यार्थियों में भारतीय संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 'संविधान जागरूकता प्रश्नोत्तरी 2025' का आयोजन किया जाएगा। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (बार्टी) और आदिवासी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (टीआरटीआई) इस राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान करें, यह निर्देश महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम ने दिया।

संविधान प्रश्नोत्तरी जागरूकता अभियान के संबंध में आयोग कार्यालय में उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। वे इस अवसर पर बोल रहे थे।

टीआरटीआई आयुक्त दीपा मुधोल-मुंडे और बार्टी के महानिदेशक सुनील वारे ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे इस पहल के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराकर प्रतियोगिता के सफल कार्यान्वयन में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम ने बताया कि आयोग की पहल पर कक्षा 8 से 12 तक और स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए यह प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाएगी। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय संविधान और उसके मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

मेश्राम ने विद्यार्थियों के लिए संविधान पर आधारित तीन भाषाओं में पाठ्यक्रम तैयार करने और जिला एवं राज्य स्तर पर समन्वय करके प्रश्नपत्र तैयार करने के भी निर्देश दिए। स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों की आयु वर्ग के अनुसार संविधान के प्रश्नपत्र के बारे में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम ने कहा कि सभी संबंधित विभाग इस पहल की प्रगति, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया और कार्यान्वयन की विस्तृत जानकारी राज्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रस्तुत करें।

बैठक में आयोग के सदस्य गोरक्ष लोखंडे, आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के अनुसंधान अधिकारी विजय गुंड, आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालय नासिक के सहायक परियोजना अधिकारी अनिल महाजन, बार्टी के परियोजना प्रबंधक सुमेध थोरात, युवा कैरियर संस्थान के मुनाल थुल, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नागपुर की प्रोफेसर आरती तायडे और एसोसिएट प्रोफेसर दिविता कोठेकर के साथ-साथ संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

महिला खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम की सुविधा - खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एडवोकेट माणिकराव कोकाटे

खेल परिसरों, खेल क्लबों, जिमखानों, स्टेडियमों और खेल के मैदानों में सुविधाएँ

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। सरकार ने राज्य की महिला खिलाड़ियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एडवोकेट माणिकराव कोकाटे ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी है कि राज्य के सभी खेल परिसरों, खेल क्लबों, जिमखानों, स्टेडियमों और स्थानीय खेल के मैदानों में महिला खिलाड़ियों के लिए अलग, स्वच्छ और सुरक्षा-युक्त चेंजिंग रूम की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

कुछ दिन पहले, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने दादर जिमखाना के नवीनीकरण का उद्घाटन करते हुए महिलाओं से देश भर के खेल परिसरों में चेंजिंग रूम की सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की थी और कहा था कि महिलाओं को खेल के मैदान में सुरक्षित

और सम्मानजनक वातावरण मिलना चाहिए।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री एडवोकेट माणिकराव कोकाटे इस अपील पर तुरंत और सकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाले देश के पहले मंत्री बन गए हैं।

खेल मंत्री एडवोकेट कोकाटे ने कहा कि राज्य भर की महिला खिलाड़ियों को सुरक्षित और सम्मानजनक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए इस योजना को तुरंत लागू किया जाएगा। ये सुविधाएँ हर ज़िले, तालुका और स्थानीय खेल के मैदान में प्राथमिकता के आधार पर स्थापित की जाएँगी।

शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाओं और आवश्यक सुरक्षा के लिए सीमित क्षेत्रों में चेंजिंग रूम में सीसीटीवी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही, प्रत्येक स्थान पर महिला सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं। खेल मंत्री श्री कोकाटे ने पुराने भवनों की मरम्मत या नए चेंजिंग रूम बनाने के प्रस्ताव तुरंत प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय से न केवल सुविधाएँ मिलेंगी, बल्कि खेल क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

खेल मंत्री एडवोकेट कोकाटे ने कहा कि खेल के मैदान में अब हर लड़की गर्व के साथ कदम रखेगी। हर सफलता के पीछे एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल की मज़बूत नींव होगी। इस निर्णय से राज्य में महिला खिलाड़ियों के लिए एक नया अध्याय शुरू होगा और महाराष्ट्र महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ा रहा है।

सम्पादकीय

डिजिटल धोखाधड़ी बनती जा रही है हमारे लिए एक गंभीर समस्या, सख्त कानूनों के बावजूद आम लोग हो रहे शिकार

तेजी से बदलते दौर में नई तकनीकों के उपयोग को वक्त की जरूरत के तौर पर देखा जा रहा है। इसी क्रम में आम जिंदगी में संवाद से लेकर पढ़ाई-लिखाई और लेन-देन जैसे तमाम मामले अगर डिजिटल तकनीक के दायरे में आ रहे हैं तो यह स्वाभाविक है। इसी के मद्देनजर 'डिजिटल इंडिया' का नारा भी दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट आधारित तकनीकों के उपयोग के प्रति आकर्षित हों। विडंबना यह है कि जिस तेजी के साथ डिजिटल यंत्रों का उपयोग बढ़ा है, उसी अनुपात में इसमें सुरक्षित गतिविधियों का ढांचा विकसित नहीं हुआ है।

इससे उपजने वाले जोखिम रोज नए और जटिल स्वरूप में सामने आ रहे हैं। अमूमन हर रोज देश के किसी हिस्से से डिजिटल धोखाधड़ी की खबरें आती हैं और उसमें किसी की मेहनत की कमाई के लाखों रुपए अलग-अलग तरीके से लूट या उड़ा लिए जाते हैं। ऐसे मामले आम हैं, जिनमें सिर्फ किसी को फोन पर की जाने वाली बातचीत में उलझा कर उसे धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। सवाल है कि अगर देश में आधुनिक तकनीकों का विस्तार किया जा रहा है तो क्या इससे बचाव के इंतजामों को भी उतना ही अहम माना जा रहा है।

गौरतलब है कि बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी हमारे लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, इसलिए इस पर अंकुश लगाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है। हालांकि डिजिटल फर्जीवाड़े के मामलों में कोई अचानक उफान नहीं आया है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे यह साफ है कि आधुनिक तकनीक जितनी सुविधाजनक है, उतना ही यह जोखिम का वाहक भी बन रही है। किसी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आता है और वह व्यक्ति बातों के जाल में इस कदर फंस जाता है कि अपने बैंक खाते से खुद ही लाखों रुपए भेज देता है। इसके कुछ ही पल बाद जब उसे अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में पता चलता है, तब तक देर हो चुकी होती है। पिछले कुछ समय से ऐसे मामले आम होते देखे गए हैं, जिसमें अनजान नंबर से आए फोन काल के जरिए किसी व्यक्ति को डरा-धमका कर 'डिजिटल कैद' की स्थिति में डाल दिया जाता है और फिर भयादोहन करके उसके बैंक खाते में जमा रकम को उड़ा लिया जाता है। अब ऐसी घटनाएं कोई नई नहीं रह गई हैं, लेकिन इसमें तेजी से होते इजाफे ने यह सवाल पैदा किया है कि जिन डिजिटल संसाधनों का विकास सुविधाजनक और सुरक्षित लेनदेन और अन्य गतिविधियों के लिए किया गया, आज उसी से उपजे खतरे से निपटने के तौर-तरीके आम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि आर्थिक भ्रष्टाचार से लेकर अन्य आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने या उन्हें खत्म करने के दावे के साथ डिजिटल दुनिया का विस्तार किया गया, कुछ जगहों पर व्यवहार में इसे अनिवार्य बना दिया गया, मगर आज हालत यह है कि सख्त कानूनों के बावजूद फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह साइबर संजाल में रोज नए तरीके अपना कर आम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं।

हालांकि एक समस्या डिजिटल यंत्रों के उपयोग में लापरवाही से लेकर प्रशिक्षण की सीमा की भी है, लेकिन इससे साइबर सुरक्षा का सवाल बेमानी नहीं हो जाता। निश्चित रूप से 'डिजिटल इंडिया' एक आकर्षक नारा है, लेकिन अगर इसमें जोखिम का पैमाना इतना ही ऊंचा रहता है, तो इसकी कामयाबी संदिग्ध ही रहेगी।

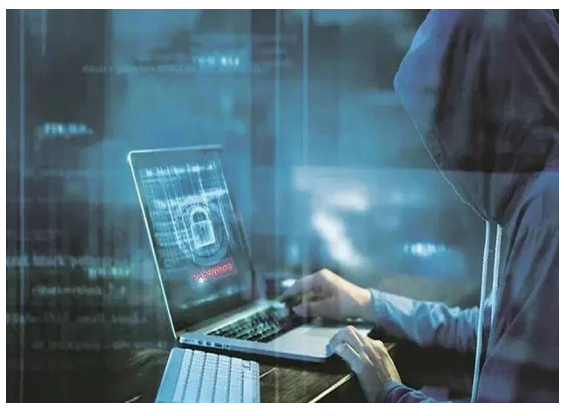

बुर्का-हिजाब बैन, मस्जिदों पर ताले! राहुल के ननिहाल में पीएम मोदी की दोस्त का बवाल, हिली इस्लामिक देशों की जमीन

राहुल गांधी के नानी के घर और सोनिया गांधी के मायके में इन दिनों भयंकर बवाल मचा है। इटली की राजनीति में इन दिनों बड़ा तूफान आया है। तूफान की चपेट में बुर्का, मस्जिदें और धार्मिक स्वतंत्रता हैं। इसका सीधा संबंध भारत की राजनीति से भी जुड़ता है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का खास दोस्त बताया जाता है। उन्होंने अब ऐसा कदम उठाया है। जिससे यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया की सियासत गर्मा गई है। मेलोनी सरकार बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। यानी इटली में बुर्का बैन होगा। वैसे तो दुनिया में 24 देश ऐसे हैं जिन्होंने बुर्का और हिजाब पर बैन लगाया हुआ है। कई देश तो ऐसे हैं जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उन्होंने भी धर्म निरपेक्षता के नाम पर अपने यहां बैन लगाया है। ऐसा ही एक नाम अब इटली का सामने आया है। इटली में जसि तरह से पिछले दिनों फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगे और सड़कों को जाम किया गया। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। उन तस्वीरों ने और ज्यादा इटली के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर देश के भविष्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए। जिस इटली को राहुल गांधी का ननिहाल कहा जाता है वहां अब मोदी की दोस्त ने ऐसा सियासी पासा फेंका है जो सीधे तौर पर भारत के कट्टरपंथियों की भी हवा निकाल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या यूरोप में अब नए सांस्कृति टकराव की शुरुआत हो चुकी है। पहले जो फ्रांस में देखने को मिला वो अब इटली में देखने को मिल रहा है। क्या मेलोनी का ये कदम भारत की राजनीति में भी गूंजेगा?

इटली की सत्ता संभालने वाली

जॉर्जिया मेलोनी ने संसद में एक बिल पेश किया है। इस बिल में कहा गया है कि देशभर में बुर्के पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। स्कूल, दुकानें हो या ऑफिस हर पबल्कि प्लेस पर अब चेहरा ढकना जुल्म माना जाएगा। मस्जिदों की फंडिंग पर निगरानी होगी। इसके अलावा जबरन धार्मिक विवाह पर रोक होगी। नकाब पहनने पर भारी जुर्माने का प्रावधान इस बिल में शामिल है। इटली की सत्तारूढ़ पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली की तरफ से कहा गया हैंकि देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर नकाब और बुर्का से चेहरा और शरीर ढकने पर प्रतिबंध लगेगा। हालांकि ये प्रतिबंध अभी भी देश के कुछ हिस्सों में है। लेकिन इस विधेयक के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। पार्टी ने इस्लामी अलगाववाद के खिलाफ विरोध विधेयक बताया है। विधेयक के योजनाकारों में सांसद एंड्रिया डेल मास्ट्रो ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता पवित्र है। लेकिन इसा खुलेआम प्रयोग हमारे संविधान और इटली राज्य के सिद्धांतों का पूरा सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए।

ओपन बॉर्डर पॉलिसी को इटली के अलावा और भी कई यूरोपीय देशों ने अपनाई थी। जिसकी वजह से पिछले 20-25 सालों में वहां बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी गए हैं। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। पालिटिको की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंध के तहत दुकानों, स्कूलों और दफ्तरों समेत सभी सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर रोक होगी। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर 300 से 3 हजार यूरो यानी लगभग 3 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने देश में बढ़ते इस्लामीकरण का आरोप लगाया। इस्लामी प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन को सांस्कृतिक अलगाववाद के रूप में बताया है।

बुर्का बैन के साथ-साथ इसी बिल में स्जिदों की फंडिंग को भी नियंत्रित करने प्रावधान है। ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी इमीग्रेशन प्रमुख सारा कैलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बिल के बारे में बताया। उन्होंने कहा यह एक ऐसा विधेयक है जो मुख्य तौर पर मस्जिदों की फंडिंग को अनियमित करने और पूरे चेहरे को ढकने वाले नकाब के उपयोग को रोकने और उस पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित होगा। यह जबरन शादी के विरुद्ध कानून पर भी जोर देता है। केलानी ने आगे कहा कि हम इटली में अपने कानूनों को लागू करते हैं जो विशिष्ट मूल्यों पर आधारित है। डेल मास्टरों ने कहा कि इटली ने फ्रांस से प्रेरणा ली है जो 2011 में बुर्के पर बैन लगाने वाला पहला यूरोपीय देश था। इसके बाद बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और यूरोप के कई देशों ने इस पहल की शुरुआत की। इस्लाम से संबंधित महिलाओं के कपड़ों पर पूर्ण का आंशिक प्रतिबंध लगा दिया।

इटली की कुल आबादी लगभग 60 मिलियनयन है। जिसमें से मुस्लिम आबादी 17 लाख से लेकर 27 लाख बताई जा रही है। जो कुल आबादी का लगभग 5 फीसदी होने का अनुमान है। आईएसएमयू 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी निवाशियों में से जितने भी प्रवासी इटली आए हैं उनमें 30 फीसदी मुसलमान हैं, जो मोरक्को, अल्बानिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हुए हैं। पीयू रिसर्च के अनुसार 2.3 से 2.7 मिलियन तक ये आंकड़ा हो सकता है। ये अपने आप में डराने वाला आंकड़ा है। यूरोप के कुछ देशों में पिछले दो तीन सालों से विशेषकर फ्रांस में जिस तरह से तांडव देखने को मिला। 2023 में हफ्ते भर तक फ्रांस जलता रहा था, जिसका एक बड़ा कारण ओपन बॉर्डर पॉलिसी को बताया गया था।

नया बिल सिर्फ चेहरा ढकने वाले कपड़ों तक सीमित नहीं है। इसमें उन धार्मिक संगठनों पर भी निगरानी की बात कही गई है जो इटली की सरकार के साथ औपचारिक समझौते में नहीं है। फिलहाल इस्लाम को इटली में वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। जबकि 13 अन्य धर्मों के पास यह अधिकार है। इसलिए यह बिल मुस्लिम संगठनों को अपने फंडिंग सोर्सेज सार्वजनिक करने और संदिग्ध फाइनेंसरों से दूरी रखने को अनिवार्य करता है। इसके साथ यह कानून वर्जिनिटी टेस्ट कराने वालों पर भी सजा का प्रावधान लाता है और जबरन धार्मिक विवाहों में धार्मिक दबाव को अपराध की श्रेणी में लाता है। फिलहाल इटली की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के पास संसद में पूर्ण बहुमत है। इसलिए इस बिल के पारित होने की संभावना बेहद मजबूत है।

इटली से इतर भारत में हिजाब और बुर्के का मुद्दा लगातार चर्चा में रहता है। कॉलेजों में हिजाब के मुद्दे को लेकर ये अदालत के दरवाजे तक भी पहुंच चुका है। हालांकि भारत में बुर्का बैन होना फिलहाल संभव नहीं लगता क्योंकि यह बेहद संवेदनशील और विवादास्पद विषय है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर राष्ट्र है जहां संविधान द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी गारंटी दी जाती है। जिसका सीधा फायदा कट्टरपंथी उठाते भी हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच बीजेपी ने अचानक बुर्का बैन की मांग उठाकर सियासी तापमान बढ़ाया था। इससे विपक्षी पार्टी खासकर आरजेडी और कांग्रेस बहुत परेशान हो उठी थी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वोटिंग केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने की अनुमति से पहचान छिपाने और फर्जी वोटिंग की आशंका बढ़ती है।

राजनीति कभी मानी जाती थी लोकसेवा का माध्यम शिक्षा का उद्देश्य केवल रोटी-रोजगार की गारंटी भर नहीं

हमारे समय का सबसे बड़ा संकट यह है कि हम अपनी जड़ों से कटते हुए आधुनिकता और प्रगति की चकाचौंध में अपनी पहचान खोते चले जा रहे हैं। यह त्रासदी केवल व्यक्ति स्तर पर नहीं, समाज और राष्ट्र स्तर पर भी दिखाई देती है। एक तरफ तकनीक, शिक्षा, राजनीति और भौतिकता का विस्तार हो रहा है, तो दूसरी तरफ संस्कृति, परंपरा और मूल्य बिखरते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह पहचान खोने का दौर है, जहां व्यक्ति अपने भीतर से खाली होता जा रहा है और समाज अपनी आत्मा से।

शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार पाना या रोटी-रोजगार की गारंटी भर नहीं है। शिक्षा का मूल स्वरूप व्यक्ति में विवेक, संवेदनशीलता, सृजनशीलता और आत्मविश्वास जगाना होता है। लेकिन आज शिक्षा अब केवल अंक, डिग्री और पैकेज का पर्याय बनकर रह गई है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से निकलने वाले छात्र किसी मशीन की तरह प्रशिक्षित तो हो रहे हैं, पर उनमें मनुष्यता घटती जा रही है। वे अपनी जमीन, अपने गांव, अपनी संस्कृति से अनजान रह जाते हैं। उनकी सोच उपभोक्तावाद से संचालित होती है। दुर्भाग्य यह है कि आज शिक्षा व्यक्ति को 'उपभोक्ता' तो बना रही है, 'संस्कारवान नागरिक' नहीं।

शिक्षा के द्वारा नैतिकता और चरित्र का विकास होना चाहिए, लेकिन हो रहा है उल्टा। यह एक विसंगति है। तर्कशास्त्र का एक शब्द है- विपर्यय यानी विपरीत ज्ञान। जैसे चमकती हुई रेत पानी का आभास कराती है, दूर से चमकती हुई सीपी चांदी का भ्रम पैदा करती है और अंधेरे में पड़ी हुई रज्जु या रस्सी सांप जैसी दिखाई देती है। यह विपर्यय है। विद्या के अध्ययन के द्वारा नैतिकता और चरित्र का विकास होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व के परिदृश्य पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि अपराध में पढ़े-लिखे और पैसे वाले लोग भी लिप्त हैं।

कम पढ़े-लिखे या अनपढ़ आदमी में इतनी चालाकी नहीं होती कि वह बारीक योजना बनाए, जिससे किसी को पता न चले और वह कानून की पकड़ से बाहर रहे। पढ़-लिख लेने के बाद चालाकी और क्षमता तो आ जाती है, लेकिन उसी मात्रा में नैतिकता का विकास नहीं होता। बुद्धि का विकास हो और नैतिकता का विकास न हो, तो आदमी सड़क खोद कर गड्ढा करके वहां कीचड़ पैदा करेगा और फिर गाड़ी फंसने पर लोगों से पैसे वसूल कर उनकी गाड़ियां निकलवाएगा। जानबूझकर समस्या पैदा करने, उसमें दूसरे लोगों को फंसाने और पैसे लेकर उन्हें समाधान देने के लिए लोग बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं। हमने बुद्धि को अंतिम विकल्प और सीमा मान लिया, यही सारी समस्याओं की जड़ है।

राजनीति कभी लोकसेवा का माध्यम मानी जाती थी, अब वह सत्ता-सुख और स्वार्थ-सिद्धि का औजार बन चुकी है। राजनीति का लक्ष्य अब जनता की समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि जातीय, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक समीकरणों पर टिके रहना है। राजनीतिक दल मूल्यों पर बहस करने के बजाय चुनावी गणित साधने में व्यस्त हैं। आधुनिकता का अर्थ अगर वैज्ञानिक सोच, समानता और नए विचारों का स्वागत है तो यह स्वागतयोग्य है। पर जब आधुनिकता केवल उपभोग, फैशन और प्रदर्शन तक सिमट जाए तो यह आत्मा को खोखला कर देती है। आज का युवा अपने मोबाइल और सोशल मीडिया में इतना डूबा है कि उसे लोकगीत, लोकनृत्य, लोककला की कोई खबर नहीं। घर-आंगन में गाए जाने वाले मंगलगीत, तीज-त्योहार की पारंपरिक उमंग और पड़ोस की साझी संस्कृति सब खोती जा रही है। संस्कृति का स्थान अब मनोरंजन चैनल मोबाइल और ऐप ले चुके हैं। त्योहार का अर्थ मिलन और उत्सव नहीं रहा, बल्कि 'सेल' और 'रियायती आकर्षण' हो गया है। भौतिक संपन्नता को ही जीवन की सफलता मान लिया गया है। बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान और बैंक में पैसे ही आज की उपलब्धि के मानक हैं। इस दौड़ में रिश्तों की ऊष्मा, परिवार की आत्मीयता और सामाजिक जिम्मेदारी पिछड़ गई है। संस्कृति हमें संयम, सादगी और संतोष का पाठ पढ़ाती थी। लेकिन भौतिकवाद हमें असीमित इच्छाओं का दास बना रहा है। उपभोक्तावाद की इस दौड़ ने हमें प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या में उलझा दिया है। संस्कृति केवल नृत्य, संगीत या परंपराओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब संस्कृति टूटती है तो समाज की आत्मा घायल होती है। आज स्थिति यह है कि गांव के चौपाल, मंदिर-मस्जिदों की साझी संस्कृति, आपसी मेल-मिलाप, और सामूहिकता का भाव खत्म हो रहा है। उनकी जगह कृत्रिमता और निजी स्वार्थ ले रहे हैं। जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारी पहचान खो जाती है। यही पहचान का संकट आज हर तरफ दिखता है। इस त्रासदी का समाधान हमारी शिक्षा, राजनीति, आधुनिकता और भौतिकता में संतुलन से निकलेगा। शिक्षा में रोजगार के साथ संस्कार और संवेदना को जोड़ना होगा। आधुनिकता का अंधानुकरण नहीं, विवेकपूर्ण स्वीकार करना होगा। और भौतिकता को साधन मानकर संयमपूर्ण उपयोग करना होगा।

पद-प्रतिष्ठा, सत्ता आदि ऐसे उन्माद हैं, जिनके आगे पढ़ाई-लिखाई सब नाकाम हो जाते हैं। जब तक उसे सकारात्मक भाव का विकास नहीं होता, चरित्र या नैतिक मूल्यों के विकास की कोई आशा नहीं की जानी चाहिए। आज की यही सबसे बड़ी समस्या है कि चरित्र का विकास हम बौद्धिक ज्ञान से करना चाहते हैं। यह संभव नहीं। हमारा चरित्र पक्ष, आचार पक्ष ही हमारी श्रेष्ठता पर मुहर लगाएगा, ज्ञान की बात तो बाद की है। ईमानदारी की पूछ और परख गुजरे जमाने में भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। यह ऐसी निधि है, जिसकी कीमत कभी घट नहीं सकती।

सूखती नदियां और संरक्षण की राह, हजारों परिवारों को बेघर कर देती है मानसून में प्रलयंकारी बाढ़

पिछले कुछ दशकों से देश में नदियों और अन्य सहायक नदियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कहीं झरने सूख गए, तो कहीं नदियों का बहाव इतना कम हो गया कि उनकी जीवंतता पर संकट मंडरा रहा है। गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियों से लेकर हमारी क्षेत्रीय नदियां कई स्थानों पर बांध, अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण अपना मूल स्वरूप खो चुकी हैं। मध्यप्रदेश जिसे 'नदियों का मायका' कहा जाता है, वहां भी आज कई नदियों के उद्गम स्थल विलुप्त होने के कगार पर हैं।

वास्तव में मनुष्यों ने अक्सर अपनी सुविधा और औद्योगिक विकास की प्राथमिकता में नदियों को नजरअंदाज किया है। पिछले बीस वर्षों में नर्मदा और अन्य नदियों के किनारे फैली औद्योगिक इकाइयों ने जल स्रोतों को प्रदूषित किया और गोधूलि जैसी कई छोटी नदियां और जलधाराएं सूखती गईं। आधुनिक प्रौद्योगिकी के दौर में कृत्रिम मेधा (एआइ) इस संकट से नदियों को बचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

भारत में नदियां केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का जीवंत प्रतीक भी हैं। ऋग्वेद में सरस्वती को महती नदी के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि गंगा और यमुना को पुराणों तथा महाकाव्यों में देवी एवं जीवनदायिनी का दर्जा दिया गया है। गंगा स्नान को आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग बताया गया है। महाकुंभ का आयोजन इस बात का प्रमाण है कि नदियों का महत्त्व केवल जल की आपूर्ति तक सीमित नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा है। इसलिए देश में नदियों का संरक्षण केवल जल संकट की समस्या हल करने के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। सिंध, क्षिप्रा, बनास और कूनो जैसी नदियां भले ही प्रदूषित नदियों की श्रेणी में न आती हों, लेकिन किनारे पर पसरी गंदगी, औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट के निस्तारण का अभाव, अतिक्रमण और जल स्तर में कमी यह संकेत देती हैं कि यदि संरक्षण के ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वक्त की कल्पना की जा सकती है। इन नदियों का महत्त्व जल आपूर्ति तक सीमित नहीं है। वे कृषि, पारिस्थितिकी, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का आधार हैं। नदियों पर संकट के कई कारण हैं। कारखानों और घरों से निकलने वाले अपशिष्ट सीधे नदियों में मिलते हैं, जिससे पानी जहरीला हो जाता है। अवैध रेत खनन और अतिक्रमण नदियों के किनारे प्राकृतिक ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पानी की उपलब्धता खत्म होने का खतरा बढ़ जाता है।

यह कोई छिपी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना बड़े स्तर पर प्रदूषण की मार झेल रही हैं। दिल्ली से गुजरती यमुना का पानी इतना दूषित है कि उसे सुरक्षित नहीं माना जाता। प्रतिदिन लाखों लीटर गैर-उपचारित अपशिष्ट सीधे इसमें गिरता है। गंगा की सहायक नदियां जैसे गंडक और घाघरा अतिक्रमण तथा रासायनिक प्रदूषण से लगातार प्रभावित हो रही हैं। बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदियां कोसी तथा बागमती अब अपने असामान्य बाढ़ चक्र और प्रदूषण के लिए जानी जाती हैं। मानसून में प्रलयंकारी बाढ़ हजारों परिवारों को बेघर कर देती है, जबकि गर्मियों में यही नदियां सिकुड़ जाती हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में गोदावरी और ताप्ती नदी की स्थिति चिंताजनक है। नासिक और अन्य शहरी क्षेत्रों से निकलने वाला औद्योगिक अपशिष्ट गोदावरी को प्रदूषित कर रहा है। ताप्ती के कुछ हिस्सों में जल इतना दूषित है कि मछलियां और अन्य जलीय जीव लगभग लुप्त हो चुके हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र की छोटी नदियां तो सूखे की वजह से केवल कागजों पर ही बची हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018-19 में देश में जल निकायों की गणना कराई थी। इसमें लगभग 24.24 लाख तालाब, झीलें, जलाशय जैसी संरचनाओं और कृत्रिम जल स्रोतों को चिह्नित कर उनकी स्थिति का पता लगाया गया। इस पहल से यह स्पष्ट हुआ कि किस राज्य में कितने जल स्रोत हैं और उनमें से कितने उपयोगी हैं तथा कितने अतिक्रमण या सूखने के कगार पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय जल आयोग की समय-समय पर रपट यह बताती रही है कि देश की अधिकांश प्रमुख नदियों विशेषकर गंगा, यमुना, साबरमती और गोमती का जल स्वच्छता मानकों से काफी नीचे है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों से स्पष्ट है कि दिल्ली में यमुना की हालत बेहद खराब है। इसमें प्रदूषण की वजह से जल की गुणवत्ता का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। मार्च 2025 में यमुना में फास्फेट और औद्योगिक अपशिष्ट की मात्रा पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक पाई गई।

दूसरी ओर छोटी नदियों का अपना महत्त्व है। ये बड़ी नदियों का आधार हैं और अपने क्षेत्र की बड़ी आबादी के जीवन को सींचती हैं। इनके संरक्षण के लिए जितना जरूरी सरकारी प्रयास हैं, उतना ही समाज की सक्रिय भागीदारी भी है। इसमें दोराय नहीं कि आज के तकनीकी दौर में कृत्रिम मेधा नदियों के संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकती है। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों, ड्रोन से निगरानी और 'रीयल-टाइम डेटा एआइ माडल' के जरिए नदियों के जल स्तर, बहाव और प्रदूषण की स्टीक जानकारी मिल पाती है। इसका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किए जाने से समय रहते उचित कदम उठाए जा सकते हैं। 'गूगल अर्थ' और अन्य एआइ उपकरण नदियों के बदलते स्वरूप और प्रवाह का रेकार्ड रखने में मदद करते हैं। 'वाटरसिम' और 'रिवरवेयर' जैसे कृत्रिम मेधा माडल बाढ़ और सूखे की समय रहते चेतावनी देने में सक्षम हैं।

कृत्रिम मेधा आधारित मोबाइल एप और अन्य मंच नागरिकों को अपनी नदियों की स्थिति का पता लगाने का अवसर देते हैं। इनकी मदद से लोग नदी किनारे प्रदूषण, जल स्तर में बदलाव या अतिक्रमण की जानकारी तुरंत साझा कर सकते हैं। स्मार्ट सेंसर और अन्य कृत्रिम मेधा उपकरण जल गुणवत्ता, रासायनिक प्रदूषण और जैव विविधता की निगरानी करते हैं। इसके अलावा कृत्रिम मेधा आधारित शिक्षा और जन-जागरूकता मंच भी बनाए जा सकते हैं। बच्चों और युवाओं में यह संदेश फैलाया जा सकता है कि नदियां केवल पानी की धारा नहीं, बल्कि जीवन और संस्कृति का आधार हैं। जब समाज के हर वर्ग को इसका महत्त्व समझ आएगा, तभी नदियों का संरक्षण स्थायी रूप से संभव हो पाएगा।

कई देशों में कृत्रिम मेधा का नदियों और अन्य जल स्रोतों को बचाने के लिए पहले से ही उपयोग हो रहा है। ब्रिटेन में यूनिवर्सिटी आफ शेफील्ड और सीमेंस की साझेदारी में क्लाउड-आधारित एक कृत्रिम मेधा की प्रणाली विकसित की गई है, जो सीवेज पाइप में अवरोध का पता लगाने में मदद करती है। इससे नदियों में अपशिष्ट के अनियंत्रित प्रवाह और प्रदूषण को रोकने में मदद मिल रही है। हालांकि देश में इस काम के लिए तकनीक का होना ही पर्याप्त नहीं है। नीति निर्धारकों और प्रशासन को कृत्रिम मेधा उपकरणों से मिलने वाली जानकारी का सही इस्तेमाल करना होगा। नदियों के संरक्षण के लिए कानूनी, प्रशासनिक और सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता होगी। तकनीक के साथ आम नागरिकों की जागरूकता और सरकार की नीतियां मिल कर नदियों को नया जीवन दे सकती हैं। यह न केवल जल संरक्षण, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक अमूल्य धरोहर होगी।

बच्चों को पानी के बचाव हेतु कार्यक्रम का हुआ आयोजन, प्लांट का हुआ भ्रमण

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। जल स्वच्छता मिशन के क्रियान्वयन हेतु फिकल स्लज़ एव सेप्टेज़ प्रबंधन प्रोग्राम के अंतर्गत जलकल विभाग नगर निगम प्रयागराज एवम् युवा सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से आर. के इंस्टिट्यूट ऑफ़ फार्मेसी नैनी प्रयागराज कॉलेज में मलासूर से पानी के बचाव तथा हर 03 साल में जरूर सेप्टिक टैंक साफ करवाओ विषय पर कॉलेज बच्चों को जानकारी दी गई तथा उनके बीच कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया तदोपरांत सभी बच्चों को भौतिक जानकारी के लिए नैनी प्रयागराज स्थित प्लांट का भ्रमण भी कराया गया।

उक्त अभियान में जलकल विभाग के अधिशाषी अभियंता सौरभ सिंह, यश. पी सिंह तथा युवा सामाजिक सेवा संस्थान के सचिव आलोक शुक्ला संस्था की सदस्य श्रीमति मीरा सिंह ऋषभ तिवारी तथा मुकेश शुक्ला साथ में कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर सी. यश सिंह वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर दिलीप कुमार एवं प्रोफेसर अंकित मिश्रा तथा अध्यापकगण उपस्थित रहे।

सनातन हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर में कैंसर रोग के इलाज के लिए प्रयागराज में ओपीडी शुरू

ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता अभियान चलाकर लोगो को कर रहे जागरूक

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। गुरुवार को कमला नेहरू स्थित सनातन हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर में एक वार्ता आयोजित की गई जिसमें लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल के वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ हर्षवर्धन अत्रेय डायरेक्टर

मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और हेमटो-ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर रोग विशेषश्र ने पत्रकारों को वार्ता के दौरान बताया कि यह माह हम लोग कैंसर जैसे गंभीर बीमारी की रोकथाम वा आमजनमानस को जागरूक करने की मुहिम चला रहे ताकि लोगों में कैंसर जैसे गंभीर बीमारी की जानकारी हो और सही समय पर उसका उपचार शुरू कर के मौत से बचाया जा सके और वा स्वास्थ्य हो सके इन सब विषयों को लेकर डॉ हर्षवर्धन ने बताया कैंसर आज एक जानलेवा बीमारी है इसका सही समय पर इलाज व सही देखरेख से काफी हद तक होने वाली मौतों को रोका जा सकता है ।

लखनऊ मेदांता हस्पिटल आज एक नई आधुनिक तकनीक और नए उपकरण से चिकित्सक के लिए इलाज में मिल का पत्थर साबित हो रहा है।

डा हर्षवर्धन ने बताया कि अब प्रयागराज वालों को कैंसर जैसे गंभीर बिमारी की परमर्श व इलाज के लिए उनको लखनऊ व दिल्ली के चक्कर नही काटने पडेगें अब उनको प्रयागराज में ही माह के हर गुरूवार को ओपीडी शुरू की जा रही है कमला नेहरू हस्पिटल स्थित सनातन हेल्थ केयर मे जटिल व गंभीर बिमारी की ओपीडी लखनऊ मेंदता के वरिष्ठ चिकित्सक करेंगें।

डां हर्षर्धन ने कहा कि इस माह हम बेस्ट कैंसर जागरूता कार्यक्रम चला रहे है इस अवसर पर महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूक करते हुए समय पर की गई सर्तकता जीवन बचा सकती है।

उन्होने कहा कि अभी भी देश प्रदेश में जागरूकता के अभाव में उनका सही इलाज सही समय पर नही मिल पाता जिससे बिमारी पूरी तरह से बढ़ जाता है हमारा मक्सद है कि लोगों तक हम पूरी जानकारी पहुचा सके ताकि उनका सहही समय पर इलाज शुरू हो सके और उनकी जांच बचाई जा सकें।

इस मौके पर सनातन हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर व सनातन एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक ने इस शुभ अवसर पत्रकारों को सम्मनित करते हुए कहा कि सनातन हेल्थ केयर रिसर्च सेटर में हर गंभीर बिमारी के विशेषज्ञ

चिकित्सकों की टीम है हम अपने सेटर पर लखनऊ व दिल्ली के वरिष्ठ सर्जन व वरिष्ठ चिकित्सक को बुलाकर यह गंभीर व जटिल बिमारी के लिए अब प्रयागराज वालों को बाहर नही जाना होगा उनको प्रयागराज में ही सारी सुविधा मिल जायेगी। उन्होने प्रयागराज मे चिकित्सा व्यवस्था को लेकर चिंता जताइ और कहा कि अब हम अपने सनातन हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर हर माह हर गंभीर बिमारी के लिए वरिष्ठ चिकित्सक की ओपीडी शुरू कर दी है।

अन्नम प्रसादम का 5 वां वार्षिक उत्सव भव्यता के साथ संपन्न

आप सभी अपनी संस्कृति से जुड़े रहें : न्यायमूर्ति डा गौतम चौधरी

ऋषियों की साधना के बीज आज भी है मौजूद : प्रो गिरीश चंद्र त्रिपाठी

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। वैष्णव आश्रम निकेतन श्रृंग्वेरपुर में श्रृंग्वेरपुर पीठाधीश्वर श्रीमदजगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी नारायण जी महाराज के सानिध्य में विगत पांच वर्षों से चल रहे अन्नम प्रसादम के पांच वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्तिक मास अनुष्ठान का भव्य आयोजन आज श्रृंगवेरपुर धाम में। समारोह के मुख्य अतिथि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डा गौतम चौधरी थे, जबकि समारोह की अध्यक्षता बनारस हिन्दू विश्वविधायलय के पूर्व कुलपति प्रो गिरीश चंद्र त्रिपाठी थे।

अन्नम प्रसादम का 5 वां वार्षिक उत्सव कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर मनाया गया. इस विशेष कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी ने कहा कि भगवान श्रीराम ने न्याय संगत निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में सही को गलत और गलत को सही करने का प्रयास करना चाह रहे हैं उसे दूर करना है, न्याय के माप दंड स्थापित करना चाहिए, राजा दशरथ का आदेश था कि भगवान श्रीराम को वन जाना हैं और भरत को राजगद्दी मिलना चाहिए.आज कानून का पालन कैसे हो रहा हैं उसे देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम को वन वास कर्म के आधार पर गए. श्रीराम ने न्याय की व्यवस्था करने के लिए वन जाना स्वीकार किया था।न्यायमूर्ति डा गौतम चौधरी ने कहा कि भगवान श्रीराम से बड़ा नेता कोई नहीं हुआ, मै ही शुरू करूंगा और मै ही अंत करूंगा, सनातन धर्म सब धर्मों का बंधु है। उन्होंने कहा कि भारत माता की सही तस्वीर बनानी है, सभी देशों को लेकर चलना है.धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। उन्होंने कहा कि रामायण कोर्ड ऑफ कंडक्ट हैं, धर्म सिर्फ कर्तव्य बोध है.हिन्दी में 28 हजार जजमेंट दिया हैं हिन्दी मेरी माँ हैं, हिन्दी को बढ़ावा दीजिये.आप सभी अपनी संस्कृति से जुड़े रहें.

विशिष्ठ अतिथि विमल देव जी महाराज ने कहा कि वस्त्र दान प्रतिदिन करते हैं। राष्ट्रीय रामायण मेले के संयोजक उमेश द्विवेदी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए श्रृंग्वेरपुर के महात्म को बताया।विशिष्ट अतिथि बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि ऋषियों की साधना के बीज आज भी मौजूद है. भारत एक भूखंड नहीं दर्शन दृष्टि और विचार है. इसका मूल सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम है.अच्छी बात कहीं हो किसी के पास हो उसका सम्मान करना चाहिए. हमारे पूर्वजों के दिए बीज नष्ट नहीं हुए हैं उसमें वीकृति आई है उसका हमें ध्यान देना है और उसे दूर करने का प्रयास करना है.। विशिष्ठ अतिथि रामलीला कमेटी महासंघ के अध्यक्ष दुर्गेश दुबे ने कहा कि अन्नम प्रसादम का हम छोटा सा हिस्सा बन पा रहे हैं यह हमारा सौभाग्य है। जगदगुरु शांडिल्य जी महाराज ने मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति डा गौतम चौधरी सहित सभी अतिथियों को अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। संचलन डॉ शिव प्रसाद मिश्रा ने किया। इस दौरान शेष नारायण शास्त्री, कुलदीप नारायण तिवारी, भानु प्रकाश, विधाकांत पांडे, बच्चा मिश्रा, शुभम तिवारी सहित बडी संख्या मे क्षेत्रीय लोग मौजूद थे।

इफको चेयरमैन का हुआ भव्य स्वागत

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। कल इफको परिवार के लिए गौरव का क्षण रहा जब इफको के चेयरमैन दिलीप संघाणी जी का इफको सदन, नई दिल्ली में भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर का आयोजन इफको कर्मचारी संघ एवं इफको अधिकारी एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय इफको कर्मचारी संघ के चेयरमैन बृजेश कुमार तथा अखिल भारतीय इफको अधिकारी एसोसिएशन के चेयरमैन गौरव कुमार ने प्रबन्ध निदेशक के जे पटेल जी के मार्गदर्शन में अग्रणी भूमिका निभाई। इस अवसर पर इफको फूलपुर में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पंकज पांडेय, महामंत्री विजय कुमार यादव, तथा इफको फूलपुर अधिकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग तिवारी और महामंत्री स्वयम् प्रकाश ने हर्ष व्यक्त किया । उन्होंने दिलीप संघाणी जी को सच्चे सहकारी पुरुष के रूप में संबोधित करते हुए उनके प्रेरणादायक नेतृत्व और सहकारिता के प्रति समर्पण की सराहना की। दिलीप संघाणी जी का इफको एवं सहकारिता आंदोलन के प्रति योगदान अद्वितीय है। उन्होंने अपने दूरदर्शी नेतृत्व और आजीवन सेवा से 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र को साकार रूप दिया है। पूरा इफको परिवार उनके नेतृत्व पर गर्व करता है और उनके मार्गदर्शन में सहकारिता की भावना को और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मेजा ऊर्जा निगम ने स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु क्रिस्प भोपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। मेजा ऊर्जा निगम (प्रा.) लिमिटेड ने अपने नैगम सामाजिक दायित्व के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल के रूप में परियोजना के आसपास स्थित 7 ग्राम सभाओं से चयनित 80 युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु क्रिस्प (सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस), भोपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौते के तहत चयनित युवाओं को उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रोजगारोन्मुख तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हाई प्रेशर वेल्डिंग तकनीशियन, सोलर पीवी इंस्टॉलर तकनीशियन, सीएनसी मशीन ऑपरेटर, तथा सहायक फैशन डिजाइनर जैसे कौशल आधारित पाठ्यक्रम शामिल हैं। इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीकी दक्षताओं से सुसज्जित कर स्वरोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर अवसरों के लिए तैयार करना है।

इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशेष कुमार चट्टोपाध्याय ने कहा कि 'मेजा ऊर्जा निगम स्थानीय युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्रिस्प के साथ यह साझेदारी न केवल युवाओं को तकनीकी ज्ञान से सशक्त बनाएगी, बल्कि उनके करियर को एक नई दिशा प्रदान करेगी।'

यह हस्ताक्षर समारोह मेजा ऊर्जा निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशेष कुमार चट्टोपाध्याय की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें निगम की ओर से विवेक चंद्रा, अपर महाप्रबंधक (मा.स.), अजय सिंह, उप महाप्रबंधक (मा.स.), तथा क्रिस्प की ओर से पंकज तिवारी, मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव उपस्थित रहे।

संगम रोप वे का निर्माण शीघ्र होने जा रहा शुरु पीडीए ने दी जानकारी

रोप-वे के लिए तीन टावर का निर्माण, दो स्टेशन बनाए जाएंगे

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल त्रिवेणी संगम में रोप-वे निर्माण की सभी बाधाएं लगभग दूर कर ली गई है। अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो दीपावली के पहले रोप-वे का निर्माण कार्य भी शुरू हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2019 के कुंभ मेले में मंजूरी मिली थी लेकिन बजट देर से आवंटित होने के चलते इसका निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका था। इसके बाद महाकुंभ 2025 के आयोजन के चलते एक बार फिर इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू नहीं हो सका था लेकिन अब प्रोजेक्ट का मॉडल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) में बैठक के बाद अब जल्द ही रोप-वे का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के उपाध्यक्ष डॉ अमित पाल शर्मा ने आज बताया कि रोप-वे के निर्माण को लेकर एन एच, विद्युत विभाग और जलकल विभाग समेत संबंधित अन्य विभागों के साथ समन्वय बैठक कर ली गई है। उन्होंने बताया कि रोप-वे से संबंधित जो भी समस्याएं थी उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। पीडीए वीसी ने बताया कि रोप-वे के निर्माण में आ रही सभी समस्याओं पर चर्चा कर ली गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डा अमितपाल शर्मा ने बताया कि रोप-वे निर्माण के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और जल्द ही रोप-वे का निर्माण कार्य धरातल पर

दिखाई देगा। दीपावली से पहले रोप-वे का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। उन्होंने बताया कि रोप-वे के लिए तीन टावर का निर्माण किया जाना है। जबकि दो स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ अमित पाल शर्मा ने बताया कि संगम के दोनों तरफ निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम भी पूरा कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि संगम में रोप-वे निर्माण सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। महाकुंभ 2025 से पहले इसका निर्माण शुरू होना था। लेकिन उस वक्त इसका निर्माण कार्य नहीं शुरू हो सका था। रोप-वे का निर्माण परेड मैदान पर लाल और काली सड़क के बीच वाले मैदान से शुरू होगा। यह अरैल की त्रिवेणी पुष्प के पास उतरेगा। अब रोप-वे संगम से शुरू होकर शंकर विमान मंडपम और फिर अरैल जाएगा। परेड मैदान पर लाल और काली सड़क के बीच में पहला स्टेशन बनेगा। रोप-वे निर्माण के बाद त्रिवेणी पुष्प के पीछे तक पर्यटक और श्रद्धालु सफर कर सकेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से नामित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी को इसका टेंडर मिला था लेकिन अब राजस्थान की कंपनी रवि इंफ्रा बिल्ड को इसका कार्य दिया गया है। 210 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का 60 फीसदी सार्वजनिक उपक्रम वहन करेगा और शेष 40 फीसदी हिस्सा रवि इंफ्रा बिल्ड को वहन करना होगा।

सनातन एकता मिशन की ओर से गीता ज्ञान यज्ञ सम्मान समारोह संपन्न

जगदगुरु स्वामी शाडिल्य महराज, पूर्व आईएएस, जेडी, डायट प्राचार्य, डीआईओएस, अपर सचिव प्रशासन हुए

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। सनातन एकता मिशन की ओर से 'गीता ज्ञान यज्ञ सम्मान' कार्यक्रम का भव्य आयोजन जगत तारन गोल्डेन जुबिली इंटर कॉलेज के सभागार में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जगदगुरु नारायणाचार्य स्वामी शाडिल्य महराज ने किया जबकि कार्यक्रम में अतिथि पूर्व आईएएस एम एल पाण्डेय, जेडी आर एन विश्वकर्मा, डायट प्राचार्य राजेन्द्र प्रताप, यूपी बोर्ड के अपर सचिव प्रशासन एसके सिंह, डीआईओएस पीएन सिंह और एसीपी विमल मिश्रा, जेटी गोल्डेन जुबली के प्रबंधक अमित नियोगी, प्रधानाचार्या सुष्मिता कानूनगो और सनातन एकता मिशन के अध्यक्ष पं अशोक पाठक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

सनातन एकता मिशन के अध्यक्ष पं अशोक पाठक ने अतिथियों एवं विशिष्ट व्यक्तित्वों को पुष्पगुच्छ, मोतियों की माला, गीता की प्रति, अंगवस्त्र और सम्मानपत्र भेंटकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का समन्वयन सनातन एकता मिशन के महासचिव विपुलेश त्रिपाठी और कार्यक्रम संचालन डॉ. प्रभाकर त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर समाजसेवी राजेन्द्र पांडे, नीरज दीक्षित, दिलीप द्विवेदी, कल्पना पाठक, बीबी तिवारी सहित अनेक विद्वान, शिक्षक एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। सम्मानित होने वालो में पंकज जायसवाल प्रबंधक आर्यकन्या समूह, प्रो. अर्चना पाठक जी प्राचार्य आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, श्रीमती अमिता मिश्रा गुरुकुल मांटेसरी फाफामऊ, वीरेन्द्र सिंह जी प्रबंधक गुरुकुल मांटेसरी, श्रीमती सुष्मिता कानूनगो प्रधानाचार्या जगत तारन गोल्डन जुबली, श्रीमती अल्पना डे प्रधानाचार्या महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर, श्रीमती अर्चना तिवारी, प्रधानाचार्या टैगोर पब्लिक स्कूल, विजय राय जी शिक्षक टैगोर पब्लिक स्कूल, डा. योगेंद्र सिंह प्रधानाचार्य केपी इण्टर कालेज , उमेश खरे शिक्षक, धर्मेंद्र सिंह प्रधानाचार्य जीआईसी, श्रीमती नीलम मिश्रा प्रधानाचार्या जीजीआईसी, शिक्षिका डा रेखा राम जीजीआईसी, श्रीमती शशिबाला चौधरी प्रधानाचार्या जीजीआईसी, नित्यानंद सिंह जी प्रधानाचार्य ऋषिकुल विधालय, लालचंद्र पाठक प्रधानाचा य शिवचरण दास कन्हैया लाल इण्टर कालेज, विश्वनाथ मिश्रा शिक्षक, सुभाषचन्द मिश्रा प्रबंधक पं रामचंद्र मिश्रा मेमोरियल पब्लिक स्कूल, विक्रम बहादुर सिंह परिहार ज्वाला देवी इण्टर कालेज सिविल लाइंस, सरोज दुबे शिक्षक ज्वाला देवी इंटर कॉलेज, बांके बिहारी पाण्डेय प्रधानाचार्य रानी रेवती देवी इण्टर कालेज, मनोज गुप्ता, युगल किशोर मिश्रा प्रधानाचार्य ज्वाला देवी इण्टर कालेज, डा हरिप्रकाश यादव प्रधानाचार्य महर्षि कृष्ण इण्टर कालेज हण्डिया, उप प्रबंधक सचिन, प्रवीण कुमार पाण्डेय प्रबंधक मुन्नी देवी रामबालक इण्टर कालेज कोटवा, श्रीमती अनीता सोनकर शिक्षिका उठगी प्राथमिक विधालय, अजय कुमार मिश्र प्रधानाचार्य माधव ज्ञान केंद्र, खरकौनी, संजय कुमार मिश्र, राजीव कुमार मिश्रा समाज सेवी' श्रीमती रूचि तिवारी जी 'समाज सेवी है। वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला, डा सर्वेश द्विवेदी, पंकज श्रीवास्तव, सौरभ मिश्रा, विद्याकांत मिश्रा को सम्मानित किया गया। समाजसेवी पं शैलेन्द्र अवस्थी, दिवाकर मिश्रा, भोलानाथ तिवारी, जितेन्द्र तिवारी, गौरव मिश्रा मुख्य संयोजक 'कर्मयोगी पीठ' वाराणसी को सम्मानित किया गया त संचालन डा प्रभाकर त्रिपाठी ने किया।आगंतुकों के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय की प्रधानाचार्या सुष्मिता कानूनगो ने किया।

इलाहाबाद झांसी स्नातक एमएलसी चुनाव के मतदाता बनाने के लिए फार्म वितरित किए भाजपाई

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। भाजपा ने इलाहाबाद झांसी स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर मतदाता बनाने का अभियान शहर दक्षिणी विधान सभा में चलाया इस दौरान प्रवक्ता राजेश केसरवानी एवं अभियान के विधानसभा संयोजक मनोज मिश्रा के नेतृत्व में कीडगंज, मुट्ठीगंज, हटिया, कटघर, अतरसुईया, क्षेत्र के नागरिक और व्यापारियों को स्नातक एमएलसी चुनाव के मतदाता बनाने का फार्म वितरित करते हुए भरवाया। इस अवसर अजय अग्रहरि, सुनील केसरवानी, दीपक केसरवानी, शत्रुघ्न जायसवाल, नीरज केसरवानी, आदि रहे।

भिवंडी मनपा में फिर चली तबादला एक्सप्रेस

समिर जवरे बने शहर विकास विभाग प्रमुख -अरविंद घुगरे की छुट्टी

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी मनपा प्रशासन ने एक बार फिर कर्मचारियों की तबादला सूची जारी करते हुए 13 अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण किया है। इस नई सूची में सबसे प्रमुख नाम समिर जवरे, मिलिंद पलसुले और निहाला इरफान पटेल के है। जारी आदेश के अनुसार, मूल रूप से लिपिक पद पर कार्यरत समिर जवरे को शहर विकास विभाग का प्रभारी कार्यालय अधीक्षक एवं विभाग प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह वही विभाग है जो अवैध बांधकाम, जर्जर इमारतों के निष्कासन और अवैध निर्माणों पर नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार है। हालांकि यह पद परंपरागत रूप से 'बिल्डिंग कम इंस्पेक्टर' डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित माना जाता है, किंतु इस बार फिर एक लिपिक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जानकारों का कहना है कि जवरे को न तो इस विभाग का अनुभव है और न ही उन्होंने कभी

किसी प्रभाग समितियों में सहायक आयुक्त या बीट निरीक्षक पद पर कार्य किया है। इस पद पर अब तक प्रभारी अधिकारी रहे अरविंद घुगरे को उनके दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। अब वे केवल अतिक्रमण मुक्त पथक के प्रमुख के रूप में कार्यरत रहेंगे।

इसी प्रकार, मिलिंद पलसुले को क्रीडा विभाग के प्रभारी कार्यालय अधीक्षक एवं विभाग प्रमुख के आलावा उन्हें समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य अधिकारियों के तबादले इस प्रकार हैं– विनोद सकपाल को प्रभारी उपनिबंधक (जन्म-मृत्यु नोंदणी विभाग), सुनील चौहान को प्रभाग समिति क्रमांक 5 का प्रभारी कार्यालय अधीक्षक, निहाला इरफान पटेल को दूरध्वनी विभाग में प्रभारी कार्यालय अधीक्षक व विभाग प्रमुख, श्रीमती आम्रपाली सोरटे को जन्म-मृत्यु नोंदणी विभाग में लिपिक, विश्वास वाघे को स्थापना विभाग में लिपिक, श्रीमती अलका मटाले को दूरध्वनी विभाग लिपिक, प्रवीण गोडे को निवडणूक विभाग के लिपिक पद का अतिरिक्त चार्ज, अकबर शेख को प्रभाग समिति क्रमांक 1 में प्रभारी लिपिक, स्वप्निल गायकवाड़ को कर मूल्यांकन विभाग का प्रभारी सिपाही और अभिषेक घोष्टेकर को भविष्य निर्वाह निधि विभाग में सिपाही के रूप में नियुक्त किया गया है। इन सभी तबादलों को भिवंडी मनपा प्रशासक एवं आयुक्त अनमोल सागर के आदेश पर, उपायुक्त (मुख्यालय) विक्रम दराडे के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। दराडे ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल अपने-अपने नए पदों पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं।

भिवंडी में शुरू हुए अल्पावधि रोजगारपरक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम.

संत कबीर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी माध्यम से किया शुभारंभ

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

संत कबीर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिवंडी में विभिन्न अल्पावधि, नवाचारपूर्ण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी माध्यम से किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भादवड स्थित संत कबीर औद्योगिक विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक रुपेश म्हात्रे थे। इस अवसर पर भिवंडी महानगरपालिका के अधिकारी, अल्पसंख्यक समाज की प्रतिनिधि सायराबानो अंसारी, भिवंडी भाजपा उपाध्यक्ष श्रीनिवास भैरी, पालिका क्रीड़ा विभाग प्रमुख मिलिंद पलसुले, पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव विद्यालय के मुख्याध्यापक सुधीर घागस सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान की प्राचार्या सीमा महाजन ने की।कार्यक्रम में बताया गया कि यह प्रशिक्षण मात्र 100 रुपये शुल्क में पूरा किया जा सकता है और इसकी अवधि दो महीने रखी गई है। इस अवसर पर सायराबानो अंसारी ने अल्पावधि प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया और विद्यार्थियों से इन रोजगारपरक कोर्सों में अधिक से अधिक

भाग लेने की अपील की। पूर्व विधायक रुपेश म्हात्रे ने कहा कि ऐसे अल्पकालीन कोर्स युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगे।कार्यक्रम का प्रास्ताविक भाषण भरत साबले ने दिया, जबकि मंच संचालन अनिल कदम ने किया। कार्यक्रम की सफलता में प्रथम चौधरी, ज्योत्स्ना सोनटक्के और विकास पारखी का विशेष योगदान रहा।

कोनगांव पुलिस ने नागरिकों के खोए हुए मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए,खुश हुए लोग

भिवंडी। भिवंडी की कोनगांव पुलिस ने नागरिकों के खोए हुए मोबाइल फोन को बरामद करके उन्हें उनके सही मालिकों को लौटा दिया।गायब हुए फोन को वापिस पाकर लोगों के चेहरे खिल गए और सभी ने पुलिस का सराहने करने के साथ ही आभार व्यक्त किया।कोरनगाव पुलिस की तत्परता के कारण नागरिकों से 5.6 लाख रुपये से अधिक मूल्य के 25 खोए हुए मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद किया है। जो नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।सीनियर पीआई ने बताया कि केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर) पोर्टल की मदद से पिछले एक पखवाड़े में पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए लगातार प्रयासों का परिणाम हैं। सीईआईआर प्रणाली, जो आईएमईआई नंबरों के माध्यम से खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने में सक्षम बनाती है, का उपयोग कोनगांव पुलिस टीमों ने कई स्थानों से उपकरणों का पता लगाने और उन्हें पुनर्प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से किया। पुलिस उप-निरीक्षक गायकवाड़ और महिला पी.ओ. शिपाई घंडत की टीम ने यह सराहनीय काम किया। लोगों द्वारा पुलिस थानों में उनके खोने की दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर जब्त किए गए मोबाइल फोन उनके मालिकों को वापस कर दिए गए हैं।

भिवंडी मनपा में 'प्लेसमेंट पॉलिसी' से पक्षाघात !

सक्षम अधिकारी बने 'पंगु'–शहर की व्यवस्था ध्वस्त, नागरिक परेशान

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी-निजामपुर शहर महानगर पालिका में कई वर्षों से प्रशासक राजवट लागू है। नागरिकों को उम्मीद थी कि बिना राजनीतिक दबाव के प्रशासन पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से काम करेगा, परंतु हालात बिल्कुल उलट है। पिछले कुछ महीनों में पालिका के अस्थापना विभाग में अधिकारियों की नियुक्तियों और स्थानांतरण के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, उसने न केवल सक्षम अधिकारियों को पंगु बना दिया है बल्कि पूरे शहर की प्रशासनिक मशीनरी को जकड़ कर रख दिया है।

पालिका के भीतर 'प्लेसमेंट' के नाम पर हो रही यह अदला-बदली अब एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है। कुछ अधिकारियों को एक साथ दो से लेकर छह विभागों की जिम्मेदारी थमा दी गई है, जबकि कई अनुभवी और सक्षम अधिकारियों को ऐसे विभागों में भेज दिया गया है जहां उनका कोई विशेष कार्य नहीं रह गया। परिणामस्वरूप, शहर की अधिकांश मूलभूत सेवाएं– जैसे सफाई, पानी, स्वास्थ्य और सड़क व्यवस्था– अवैध इमारत तोड़क कार्रवाई ठप हो चुकी हैं।

पालिका के सुरक्षा विभाग में कार्यरत सुनील भोईर, सायरा अंसारी और राजू गोसावी जैसे अधिकारी वर्षों से निष्क्रिय बैठे है। बताया जाता है कि उन्हें 'प्लेसमेंट' के नाम पर जानबूझकर विभागीय कामकाज से दूर रखा गया है। इसी तरह जनसंपर्क विभाग और समाज कल्याण विभाग में अपनी दक्षता और अनुभव के लिए जाने जाने वाले सहायक आयुक्त मिलिंद पलसुले को उम्र के अंतिम पड़ाव में खेल व क्रीड़ा विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। कई प्रभाग समितियों में प्रभारी सहायक आयुक्त और शहर विकास विभाग के अनुभवी अधिकारी सुदाम जाधव अब वाचनालय विभाग में पदस्थ हैं, जबकि आपातकालीन विभाग के प्रमुख रहे साकिब खर्बे को उनके ही विभाग में अधीनस्थ बनाकर जानबूझकर पंगु बना दिया गया है।

इन अराजक तबादलों के चलते नागरिकों के दैनिक कार्य महीनों तक अधर में लटके रहते है। सड़कों की मरम्मत अधूरी पड़ी है, पेयजल आपूर्ति बाधित है और शहर में फैला कचरा स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। स्वच्छता विभाग की लापरवाही के कारण डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। टैक्स वसूली नगण्य है और पालिका का खजाना लगातार खाली हो रहा है। विकास कार्यों के लिए आने वाली निधि का उपयोग मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाय कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों में किया जा रहा है। पालिका के भीतर चल रही यह 'प्लेसमेंट पॉलिटिक्स' अब एक सुनियोजित तंत्र का रूप ले चुकी है। जानकारों का कहना है कि कुछ अधिकारियों को हाशिये पर रखकर चुनिंदा चेहरों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके चलते न केवल प्रशासनिक संतुलन बिगड़ गया है बल्कि नागरिकों का भरोसा भी लगातार कम हो रहा है। भिवंडी की स्थिति यह है कि विकास कार्य फाइलों में बंद हैं और शहर की समस्याएं सड़कों पर खुली पड़ी हैं। उड़ान पुलों की मरम्मत वर्षों से अधर में है, पानी की पाइपलाइनें टूट चुकी हैं और सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। दक्ष नागरिकों का कहना है कि प्रशासनिक उदासीनता ने भिवंडी को कचरे और जाम के शहर में बदल दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक महानगर पालिका में पारदर्शिता, जवाबदेही और जिम्मेदारी की भावना नहीं लौटेगी, तब तक भिवंडी का विकास केवल कागजों और बैठकों तक सीमित रहेगा। सक्षम अधिकारियों को उचित जिम्मेदारी और स्वतंत्रता दिए बिना शहर की प्रगति संभव नहीं। शहर के दक्ष नागरिकों ने मांग की है कि क्या यह 'प्लेसमेंट पॉलिसी' विकास के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुकी है, या फिर यह सिर्फ कुछ अधिकारियों की कुर्सियों को बचाने का साधन है ? समय आ गया है कि प्रशासक इस स्थिति की गंभीरता को समझें और प्रशासन को 'पंगु' होने से बचाऐ'।

मध्य रेल क्षेत्रीय रेल हिन्दी नाट्योत्सव - 2025 का आयोजन

मध्य रेल के महाप्रबंधक द्वारा पुरस्कार वितरण

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

श्री विजय कुमार, महाप्रबंधक मध्य रेल की सदस्यता दिनांक 08.10.2025 को मध्य रेल सभागृह में नाट्योत्सव का समापन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस नाट्योत्सव का उद्घाटन दिनांक 06.10.2025 को मध्य रेल सांस्कृतिक अकादमी के अध्यक्ष श्री अरविंद मालाखेड़े, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक ने दीप जौहर किया। इस नाट्य मंडलोत्सव में कुल 07वें दल ने भाग लिया जिसमें मुख्यालय सांस्कृतिक अकादमी नाटक 'अबहिन हंसा चेत सबेरा', मुंबई मंडल द्वारा 'आधे-अधूरे', नागपुर मंडल द्वारा 'मोक्ष', सोलापुर मंडल द्वारा 'कौल (फैसला), भुसावल मंडल द्वारा 'सपनों का मोबाइल', परेल मंडल द्वारा 'महादान' और माटुंगा कैबिनेट द्वारा 'जानवर' नाटक प्रस्तुत

किया गया। नाटकों के क्लासिक के रूप में सुप्रसिद्ध द्वारा निर्देशित, अभिनेता एवं सक्रिय थिएटर कलाकार शैलेन्द्र कुमार गुहिया, श्री युद्धवीर दहिया और संगीतकार पूजा इंजील को आमंत्रित किया गया था।

क्लासिक्स द्वारा घोषित नतीजों के अनुसार मुंबई मंडल द्वारा प्रस्तुत नाटक 'इदी-अधूरे' को सर्वश्रेष्ठ नाटक के रूप में रेलवे बोर्ड में नामित किया गया था और इसी नाटक के निर्देशक श्री संतोष वेरुलकर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सपनाली सांखे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में नामित किया गया था। नाट्योत्सव के सभी कलाकारों और हिंदी पखवाड़े-2025 के सफल कलाकारों को महाप्रबंधक द्वारा प्रमाण पत्र और कैश पुरस्कार प्रदान किए गए।

सभा को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक सर ने कहा कि नाट्य एक ऐसी कला है जो विकास के बाद आने वाली विधाओं में से एक है। मुंबई मंडल द्वारा पुनर्निर्मित आज के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से एक 'आधे-अधूरे' एक अद्भुत नाटक है और मेरी आशा है कि यह नाटक पूरे स्तर पर प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त करेगा। प्रधान मुख्य रक्षा अधिकारी एवं मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री चंद्र किशोर प्रसाद ने अपने स्वागत में कहा कि जिस प्रकार से मध्य रेल राजभाषा के प्रयोग-प्रसार में अग्रणी है उसी प्रकार हमारी सांस्कृतिक अकादमी के कर्मचारी भी इस क्षेत्र में अग्रणी हैं।

भिवंडी मनपा क्षेत्र में 24 घंटे जलापूर्ति बंद,पानी सप्लाई करने वाले पाइप लाइन होगा स्थानांतरित

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। भिवंडी मनपा के कई क्षेत्र में रविवार को 24 घंटे पानी सप्लाई बंद रहेगी। मनपा जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर ने बताया कि भिवंडी शहर में पानी सप्लाई करने वाली मुख्य पाइप लाइन को शिफ्ट करने का काम मानसरोवर इलाके में किया जाने वाला है।जिसके मद्देनजर शनिवार 11 अक्टूबर 2025 को सुबह 9 बजे से रविवार 12 अक्टूबर 2025 को सुबह 9 बजे तक 24 घंटे पानी सप्लाई बंद रहेगा।इसके अलावा अगले दिन कब दबाव में व कम प्रेशर से पानी सप्लाई की जाएगी।उन्होंने शहर की जनता से इस दौरान संभाल कर पानी का इस्तेमाल करें।

पद्मानगर, गायत्रीनगर, रामनगर, नवजीवन कॉलनी, बीएनएन कॉलेज रोड, पटेल कंम्पाऊंड गल्ली नं. 1,2,3, भैयासाहेब आंबेडकरनगर, न्युप्रकाशनगर, माधवनगर, सोमानगर, विठ्ठलनगर, गंगाराम वाडी, लकडाचाळ, न्यु टावरे कंम्पाऊंड, दुधबावडी, हाफिजनगर, आलमगीर विडीओ परिसर, न्यु इस्लामाबाद, आझमीनगर, खालीक शेठ चाळ दिवानशाह, हांडीकंम्पाऊंड समरुबाग, इदगाहरोड, कारीवली रोड, दर्गारोड, मोमिन बाग, कोतवालशाह, मुर्तुजा कंम्पाऊंड, धोबीतलाव, बाबु चुनिवाला बिल्डींग, टावरे वाडी, चारचाळी, हमालवाडा, तंडेल मोहल्ला, बंदर मोहल्ला, सौदार मोहल्ला, मुकरी शाह, सुतारआळी, भोईवाडा, भुसार मोहल्ला, ब्राम्हणआळी, कासारआळी, पोस्ट ऑफिस जवळ, बाजारपेठ, हफसन आळी, जैतुनपूरा, कापतलाव, समदशेठ बगीचा, बंगालपूरा, धोबी मोहल्ला, सोनापूर, तेली मोहल्ला, कॅसरबाग, ठाणारोड, बोबडे मोहल्ला, गौरीपाडा, भुसार मोहल्ला, खजुरपूरा, नाचन कंम्पाऊंड, समदनगर, कणेरी, पायल टॉकीज जवळ, अजंठा कंम्पाऊंड 1 व 2, धामनकर नाका, वॉटर सप्लाय कॉलनी, ठाणगेआळी, तीनबत्ती, फैजान कंपा., मेहता कंपाउन्ड, रोशनबाग, देऊनगर टावरे कंपाउन्ड, निजामपूरा, विठ्ठलनगर चींचेच्या झाडा जवळ, ग्लोबल कॉप्लेक्स, खालीक शेठ कंम्पाउंड रोशनबाग में पानी सप्लाई बंद रहेगा

भिवंडी के गोदामों में नहीं हो रहा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट?

बढ़ रहा आगजनी का खतरा

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी गोदामों में बार-बार लगने वाली आग की घटनाओं को देखते हुए विद्युत विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने ऐसे सभी गोदामों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने अब तक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट नहीं कराया है। अधिकारियों का कहना है कि आग लगने की ज्यादातर घटनाएं शॉर्टसर्किट या ओवरलोडिंग के कारण होती हैं, जिनका मुख्य कारण बिजली व्यवस्था की समय-समय पर जांच न होना है। भिवंडी के अंजुरफाटा, रहनाल, पूर्णा, काल्हेर और दपोड़ा जैसे इलाकों में हजारों की संख्या में गोदाम स्थित हैं। इन इलाकों में केमिकल, कपड़ा, कुरियर, इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिस्टिक्स से जुड़े गोदामों में अक्सर भीषण आग की घटनाएं होती रहती हैं। इन हादसों में करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो

जाती है और मजदूरों व अग्निशमन कर्मियों की जान जोखिम में पड़ जाती है।ठाणे डिविजन दो के सहायक विद्युत निरीक्षक जाधव ने बताया कि कई घटनाओं की जांच में सामने आया है कि अधिकतर जगहों पर केबलिंग पुरानी, अर्थिंग कमजोर और वायरिंग ओपन रहती है। साथ ही, लोड क्षमता से ज्यादा मशीनें जोड़ी जाती हैं और फायर सेफ्टी उपकरण नदारद रहते हैं। उन्होंने चेताया कि यदि स्थिति नहीं सुधारी गई तो यह पूरा क्षेत्र 'विद्युत हादसों के हॉटस्पॉट' में बदल सकता है। विद्युत निरीक्षक राजेश यादव ने बताया कि अब गोदामों के लिए वार्षिक विद्युत सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मान्य निरीक्षण रिपोर्ट के किसी गोदाम को बिजली कनेक्शन या कार्य अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, फायर और विद्युत सुरक्षा का संयुक्त निरीक्षण हर तीन महीने में किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले गोदामों पर भारी जुर्माना और बिजली आपूर्ति बंद करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यादव ने कहा कि 'इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन, संपत्ति और उद्योगों की सुरक्षा का अनिवार्य कवच है।

स्वच्छता पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत पश्चिम रेलवे द्वारा स्वच्छ परिवेश और खाद्य स्वच्छता पर विशेष ध्यान

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, कारखानों और ट्रेनों में स्वच्छता, सफाई और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 1 से 15 अक्टूबर, 2025 तक स्वच्छता पखवाड़ा 2025 मना रही है। इस अभियान के शुभारंभ और प्रारंभिक गतिविधियों के आधार पर 8वें और 9वें दिन स्वच्छ परिसर और स्वच्छ आहार पर केंद्रित पहलों के साथ अभियान आगे बढ़ा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आठवें दिन 8 अक्टूबर, 2025 को रेलवे कार्यालयों, कॉलोनियों, विश्राम/प्रतीक्षा कक्षों, विश्राम गृहों और शयनगृहों में स्वच्छता में सुधार हेतु सघन स्वच्छता/फ्यूमिगेशन अभियान चलाए गए। यात्रियों और रेलवे कॉलोनियों के निवासियों के लिए सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग करने के बारे में 70 से अधिक जागरूकता अभियान आयोजित किए गए। रेलवे कॉलोनियों में कचरा सफाई

के लिए जनभागीदारी अभियान चलाया गया जिसमें 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 50 स्टेशनों/कॉलोनियों में वृक्षारोपण और भूनिर्माण गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

नौवें दिन, स्वच्छ आहार पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें खाद्य स्वच्छता, विक्रेता स्वच्छता और उचित अपशिष्ट निपटान प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रेलवे परिसरों में गहन निरीक्षण किए गए। अधिकारियों और मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा स्वच्छता और स्वच्छ खाद्य हैंडलिंग प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगभग 100 फूड स्टॉल, फूड कार्ट, क्लाउड किचन और भंडारण क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। खानपान कर्मचारियों के बीच स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 200 से अधिक कैंटीन धारकों, रसोइयों और खाद्य विक्रेताओं की चिकित्सा और स्वच्छता जांच की गई। गतिविधि के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता और सुरक्षित खाद्य हैंडलिंग प्रथाओं पर जागरूकता भी बढ़ाई गई। बर्तन सफाई प्रक्रियाओं, कचरा निपटान प्रणाली, समग्र स्वच्छता और कर्मचारियों की चिकित्सा फिटनेस का आकलन करने के लिए रनिंग रूम, रेस्ट हाउस और कैंटीन सहित औचक निरीक्षण किए गए।

पश्चिम रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा पहल के अंतर्गत स्टेशनों, कॉलोनियों और खानपान इकाइयों में व्यापक स्वच्छता, सफाई और जागरूकता अभियान चलाए गए। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता में सुधार, सुरक्षित भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देना और सक्रिय जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना था।

पुलवामा शहीद के बेटे का हरियाणा अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयन

सहवाग ने सोशल मीडिया पर दी बधाई

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पुलवामा शहीद विजय सोरेंग के बेटे राहुल सोरेंग को किसी और ने नहीं बल्कि भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राहुल सहवाग इंटरनेशनल स्कूल से काफी जुड़े हुए हैं, जहां वह 2019 से छात्र रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद सहवाग ने शहीदों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की अपील की थी, ताकि उन्हें सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में बोर्डिंग सुविधाओं के साथ पढ़ने की अनुमति मिल सके।

सहवाग ने एक्स पर पोस्ट किया, 'राहुल सोरेंग को अंडर-19 हरियाणा टीम में चुने जाने पर बधाई। चूंकि उनके बहादुर पिता पुलवामा में शहीद हुए थे, इसलिए राहुल का समर्थन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है और मुझे उनके इस सफर पर बेहद गर्व है।'

पिछले दिसंबर में राहुल को प्रतिष्ठित विजय मर्चेंट ट्रॉफी में हरियाणा अंडर-16 टीम के लिए चुना गया था, जो उनके उभरते क्रिकेट करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उन्होंने अंडर-14 टीम में हरियाणा का प्रतिनिधित्व भी किया था। सहवाग ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि पुलवामा शहीद विजय सोरेंग जी के बेटे राहुल सोरेंग, जो 2019 में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में शामिल हुए थे और पिछले 5 वर्षों से हमारे साथ रह रहे हैं, का चयन विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए हरियाणा अंडर-16 टीम में हुआ है। इससे ज़्यादा खुशी कुछ और नहीं दे सकती। हमारे महान सैनिकों को धन्यवाद।'

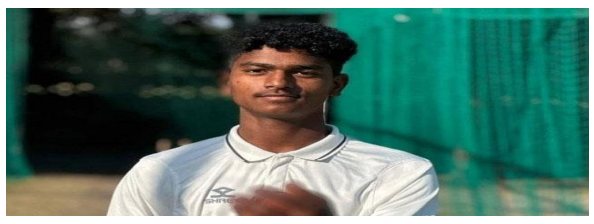

इस साल की शुरुआत में राहुल दो अन्य प्रतिभाशाली क्रिकेटरों आदित्य पांडे और शिवम आनंद के साथ करनाल के खिलाफ अंतर-जिला मैच में अंडर-19 झज्जर जिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए थे। इससे पहले सहवाग ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के बच्चों की एक तस्वीर साझा की थी, जो सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में प्रशिक्षण ले रहे थे। सहवाग ने एक्स पर पोस्ट किया था, 'वीरों के बेटे! इन दोनों को सहवाग स्कूल में पाकर और उनके जीवन में योगदान देने का सौभाग्य पाकर हम गौरवान्वित हैं। बल्लेबाज अर्पित सिंह पुत्र पुलवामा शहीद राम वकील और गेंदबाज राहुल सोरेंग पुत्र पुलवामा शहीद विजय सोरेंग। इस खुशी को कुछ ही चीजें मात दे सकती हैं।'

आईपीएल 2026 नीलामी की संभावित तारीख आई सामने, रिटेंशन की अंतिम तिथि 15 नवंबर

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। आईपीएल 2026 की नीलामी दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है, और 13-15 दिसंबर संभावित समय के रूप में उभर रहे हैं। फ्रेंचाइजी अधिकारियों, जिन्होंने बीसीसीआई अधिकारियों से बात की है। रिपोर्ट में बताया है कि चर्चा इन्हीं तारीखों पर केंद्रित है, हालांकि लीग की गवर्निंग काउंसिल ने अभी तक कार्यक्रम तय नहीं किया है। इसके अलावा इस समय इस बात का कोई संकेत नहीं है कि नीलामी विदेश में आयोजित की जाएगी, जैसा कि पिछले दो संस्करणों में हुआ था - पहले दुबई (2023) और फिर सऊदी अरब के जेद्दा (2024) में।

फ्रेंचाइजी सूत्रों का कहना है कि अगर बीसीसीआई भारत में ही मिनी-नीलामी आयोजित करने का फैसला करता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि यह फैसला अभी तक पक्का नहीं हुआ है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि रिटेंशन की समय सीमा 15 नवंबर है। तब तक, फ्रेंचाइजी को उन खिलाड़ियों के नाम जमा करने होंगे जिन्हें वे नीलामी से पहले रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। बड़े पैमाने पर बदलाव के कोई संकेत नहीं हैं, सिवाय शायद चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के, जो पिछले सीजन में सबसे निचले पायदान पर रहे थे।

रिलीज सूची में कथित तौर पर शामिल खिलाड़ियों में दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, सैम करेन और चेन्नई सुपर किंग्स के डेवोन कॉनवे भी शामिल हैं। आर अश्विन के आईपीएल से संन्यास लेने के बाद पांच बार की चैंपियन टीम के पास पहले ही 9.75 करोड़ रुपए जुड़ चुके हैं। रॉयल्स की सूची में सबसे ऊपर संजू सैमसन होंगे, जब तक कि फ्रेंचाइजी कप्तान के लिए कोई ट्रेड नहीं कर लेती।

रॉयल्स द्वारा अपने दो श्रीलंकाई स्पिनरों वानिंदु हसरंगा और महेश दीक्षाना को रिलीज करने की योजना की भी चर्चा थी, लेकिन कुमार संगकारा के मुख्य कोच के रूप में वापसी के साथ यह सोच बदल सकती है। टी नटराजन, मिशेल स्टार्क, आकाशदीप, मयंक यादव और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ियों को नई फ्रेंचाइजी की तलाश करनी पड़ सकती है, हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है - ठीक वैसे ही जैसे पिछली नीलामी में तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर के मामले में हुआ था, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था।

फ्रेंचाइजी के बीच चल रही चर्चा के अनुसार कैमरून ग्रीन के नीलामी में सबसे चर्चित नामों में से एक होने की उम्मीद है। चोट के कारण पिछली नीलामी से चूकने वाले इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने पहले ही कई टीमों का ध्यान आकर्षित कर लिया है और निश्चित रूप से उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी।

एसबीआई के एमडी, सरकारी बैंकों के ईडी पद के लिए आवेदन दे सकेंगे निजी क्षेत्र के उम्मीदवार

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष प्रबंधन पदों को निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए खोल दिया है। एसबीआई में प्रबंध निदेशक (एमडी) के चार पदों में एक पद निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए खुला है। अब तक सभी एमडी और चेयरमैन पदों पर आंतरिक उम्मीदवारों की नियुक्ति हुई है।

संशोधित नियुक्ति दिशानिर्देशों के अनुसार अब निजी क्षेत्र के लिए एक एमडी पद उपलब्ध होगा। इसी प्रकार, संशोधित दिशानिर्देशों के तहत निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में कार्यकारी निदेशक (ईडी) पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है।

एसबीआई के अलावा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया सहित 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।

इसके अनुसार निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 21 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें कम से कम 15 वर्ष का बैंकिंग अनुभव और बैंक बोर्ड स्तर पर कम से कम दो वर्ष का अनुभव शामिल है।

सार्वजनिक क्षेत्र के पद के लिए पात्र उम्मीदवार ऐसी रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इन दिशानिर्देशों के लागू होने की तिथि से एसबीआई के एमडी का पहला पद रिक्त माना जाएगा। पहली रिक्ति भरने के बाद आगामी रिक्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में काम कर रहे पात्र उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यकारी निदेशकों (ईडी) के संबंध में प्रत्येक बैंक में एक पद सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए खुला होगा, जिसमें निजी क्षेत्र के उम्मीदवार भी शामिल हैं। बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यकारी निदेशकों (ईडी) के चार पद हैं, जबकि छोटे बैंकों में दो पद हैं।

रोहित ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पूर्व साथी अभिषेक नायर की देखरेख में किया अभ्यास

मुंबई **(एजेंसी)**। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले शुक्रवार को मुंबई रणजी टीम के अपने पूर्व साथी अभिषेक नायर के साथ शिवाजी पार्क में लगभग दो घंटे तक अभ्यास किया। नायर कुछ समय पहले तक भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच भी थे। रोहित की जगह हाल ही में शुभमन गिल को भारतीय एकदिवसीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है।

रोहित 19 अक्टूबर से पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की श्रृंखला के दौरान वापसी करेंगे। ऑल हार्ट क्रिकेट अकादमी में इस अभ्यास सत्र के दौरान मुंबई के क्रिकेटर अंगकृष रघुवंशी और कुछ अन्य स्थानीय खिलाड़ी मौजूद थे। 38 साल के रोहित ने इस साल फरवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के लिए अपना पिछला मैच खेला था।

भारत ने उनकी कप्तानी में 2024 में अमेरिका और वेस्टइंडीज में टी20 विश्व कप जीत के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में लगातार दूसरा आईसीसी खिताब जीता था। रोहित के भविष्य पर लगातार सवाल उठ रहे हैं लेकिन उन्हें पुराने साथी विराट कोहली के साथ ऑस्ट्रेलिया एकदिवसीय श्रृंखला के लिए टीम में शामिल किया गया है।

दोनों महान बल्लेबाज पिछले एक साल में टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं। रोहित, कोहली और नवनियुक्त वनडे उपकप्तान श्रेयस अय्यर 15 अक्टूबर को दो अलग-अलग समूहों में ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले नयी दिल्ली में भारतीय टीम से जुड़ेंगे, जो वर्तमान में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में खेल रही है।

विराट-रोहित अजीत अगरकर की शर्तों पर सहमत न्यूजीलैंड वनडे से पहले घरेलू टूर्नामेंट में लेंगे हिस्सा

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय टीम के वरिष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के निर्देशों का पालन करते हुए आगामी विजय हज़ारे ट्रॉफी में खेलने पर सहमति जताई है। यह फैसला जनवरी में होने वाली न्यूज़ीलैंड वनडे सीरीज़ से पहले लिया गया है। अगरकर ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि हर वेंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ी, जो फिट और उपलब्ध है, उसे घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लेना होगा ताकि 2027 वनडे विश्व कप सहित भविष्य की टीम चयन प्रक्रिया में अपनी दावेदारी बनाए रखी जा सके।

चयनकर्ता अजीत अगरकर ने वरिष्ठ खिलाड़ियों के लगातार घरेलू टूर्नामेंटों से दूरी बनाए रखने पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय मैचों के बीच लंबा ब्रेक लेने वाले खिलाड़ियों को विजय हज़ारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंटों में खेलना अनिवार्य होगा। ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की घोषणा के दौरान अगरकर ने दो टूक कहा था, 'घरेलू क्रिकेट राष्ट्रीय टीम का आधार है। जो खिलाड़ी चयन की दौड़ में रहना चाहते हैं, उन्हें उसमें भाग लेना ही होगा।' रिपोर्ट के मुताबिक, कोहली और रोहित दोनों ने 24 दिसंबर से शुरू हो रही विजय हज़ारे ट्रॉफी के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि कर दी है। दोनों खिलाड़ी कम से कम तीन से चार मैच खेलने के लिए तैयार हैं। बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया, '6 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम वनडे और 11 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के बीच पाँच हफ़्तों का अंतर है।

कॉलेज में नेशनल गोल्फ प्लेयर थी रकुल प्रीत सिंह, फिल्म इंडस्ट्री में बनाई जगह

उत्तर से लेकर दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह आज 10 अक्तूबर को अपना 34वां जन्मदिन मना रही हैं। एक्ट्रेस खूबसूरत होने के साथ अभिनय कला में भी पारंगत हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में काम किया है। आज के समय में रकुल का नाम इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार है।

नई दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में 10 अक्तूबर 1990 को रकुल प्रीत सिंह का जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल से पूरी की। फिर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई की। रकुल बचपन से ही अभिनेत्री बनना चाहती थीं और उन्होंने कॉलेज के दिनों से ही मॉडलिंग करना शुरूकर दी थी। इसके अलावा रकुल का स्पोर्ट्स की ओर भी रुझान था। वह अपने कॉलेज टाइम में नेशनल लेवल गोल्फ प्लेयर थीं।

साल 2009 में अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने कन्नड़ फिल्म 'गिल्ली' से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके अलावा एक्ट्रेस कई तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। वहीं 2 साल बाद साल 2011 में एक्ट्रेस ने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। जिसमें उन्होंने अपनी जगह पांचवें स्थान पर बनाई थी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद एक्ट्रेस के पास कई हिंदी फिल्मों के ऑफर आए। रकुल प्रीत सिंह ने साल 2014 में दिव्या खोसला की फिल्म 'यारियां' से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला था।

अभिनेत्री ने अपने 15 साल के एक्टिंग करियर में कई फिल्मों में काम किया है। एक्ट्रेस ने फिल्म दे दे प्यार दे 2, दे दे प्यार दे, थैंक गॉड, मरजावा और कई साउथ की फिल्में जैसे डॉक्टर जी, देव, ध्रुवा, इंडियन 2 और किक 2 समेत कई फिल्मों में काम किया है।

एक्ट्रेस अपने फिल्मी करियर के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं। रकुल प्रीत सिंह का नाम कुछ समय पहले दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बाद इंडस्ट्री में चल रहे ड्रग रैकेट में आया था। इसके कुछ समय बाद रकुल प्रीत सिंह के भाई का नाम भी ड्रग्स रैकेट में शामिल हुआ था। वहीं अभिनेत्री ने जाने-माने प्रोड्यूसर जैकी भगनानी से शादी की है।

भारत के विनय ने पैरा पावरलिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण

काहिरा (मिस्र) **(एजेंसी)**। भारत के उभरते पैरा पावरलिफ्टिंग स्टार विनय ने काहिरा, मिस्र में आयोजित पैरा पावरलिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 के दूसरे दिन 72 किग्रा जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। विनय ने अपने तीन प्रयासों में 137 किग्रा, 142 किग्रा और 147 किग्रा की प्रभावशाली श्रृंखलाएं दर्ज कीं। उनके 147 किग्रा के अंतिम भार को रेफरी ने अमान्य घोषित कर दिया, लेकिन 142 किग्रा का उनका दूसरा सफल भार स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए पर्याप्त था जिसमें उन्होंने पोलैंड के मिकोलज कोसियुबिंस्की को, जिन्होंने 141 किग्रा भार उठाया था, मामूली अंतर से हराया।

इक्वाडोर के सेबेस्टियन एफ. ने 137 किग्रा भार उठाकर कांस्य पदक जीता। यह विनय की दूसरी बड़ी अंतरराष्ट्रीय जीत है - इससे पहले, उन्होंने मिस्र के शर्म-अल-शेख में पैरा पावरलिफ्टिंग विश्व कप 2024 में 59 किग्रा जूनियर वर्ग में 120 किग्रा भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले विनय का सफर साहस और दृढ़ संकल्प से भरा है। एक गरीब परिवार में जन्मे - उनके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं - विनय का जीवन तब बदल गया जब भारतीय पैरा पावरलिफ्टिंग टीम के कोच जे.पी. सिंह ने एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उनकी प्रतिभा को पहचाना।

सिंह के मार्गदर्शन में विनय ने अपनी क्षमता को विश्व स्तरीय प्रदर्शन में बदल दिया। यह स्वर्ण पदक न केवल भारत के लिए अपार गौरव की बात है, बल्कि लॉस एंजेलिस पैरालंपिक 2028 के लिए क्वालीफाई करने के रास्ते में विनय की स्थिति को भी मजबूत करता है। स्वर्ण पदक जीतने के बाद, उत्साहित विनय ने कहा, 'यह पदक सिर्फ मेरा नहीं है - यह हर उस व्यक्ति का है जिसने मुझ पर तब विश्वास किया जब मेरे पास कुछ नहीं था। गोरखपुर की छोटी गलियों से लेकर काहिरा के विश्व मंच तक, यह सफर आसान नहीं था। मैं भारतीय टीम के कोच जितेंद्र पाल सिंह, राजिंदर सिंह राहेलू और नितिन आर्य सर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझमें उस समय क्षमता देखी जब किसी और ने नहीं देखी थी। मैं यह स्वर्ण पदक अपने परिवार, अपने देश और हर उस युवा एथलीट को समर्पित करता हूँ जो परिस्थितियों से परे सपने देखने की हिम्मत रखता है।'

भारतीय टीम के कोच जेपी सिंह ने कहा, 'विनय की जीत कड़ी मेहनत, अनुशासन और विश्वास की सफलता का प्रतिबिंब है। जब मैं उनसे पहली बार मिला था, तब उनमें अटूट शक्ति थी, लेकिन कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था। आज, वह एक विश्व चैंपियन हैं। उनकी सफलता दर्शाती है कि सही समर्थन के साथ, भारत के पैरा एथलीट किसी भी वैश्विक मंच पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।'

महाराष्ट्र शासन

कार्यकारी अभियंता

मार्ग विकास विभाग क्र.४(सा.बां.) अंधेरी, मुंबई

भवन्स कॉलेजजवळ, दादाभाई नौरोजी, रोड,अंधेरी,(प) मुंबई-४०० ०५८

E-mail- rd4andheri.ee@mahapwd.gov.in

दुरध्वनी क्रमांक .०२२-२६२३१३११

ई- निविदा सुचना क्र.१ सन २०२५-२०२६

महाराष्ट्र राज्यपालाच्या वतीने **कार्यकारी अभियता, मार्ग विकास विभाग क्र.४, अंधेरी (प), मुंबई** - ४०० ०५८ (दुरध्वनी / फॅक्स क्रमांक २६२३१३११/२६२३१५८७) महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडील योग्य त्या वर्गातील नोंदणीकृत मुंबई उपनगर जिल्हा (पश्चिम उपनगरे) **मजूर सहकारी संस्था मर्यादित,मुंबई यांच्या कडून खालील कामाकरीता** ब -१ नमुन्यातील निविदा ई-निविदा प्रणालीद्वारे (ऑनलाईन) मागवित आहेत. निविदा कागदपत्र शासनाच्या संकेतस्थळावर www.mahatenders.gov.in येथून डाऊनलोड करण्यात यावी.

तसेच निविदा स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अधिकार कोणतेही कारण न देता सक्षम अधिकारी यांनी राखून ठेवला आहे. अट असलेली निविदा स्विकारली जाणार नाही. अर्जदार मजूर सहकारी संस्था ज्या उपनगरातील संबधीत असेल त्याच उपनगरातील कामासाठी अर्ज करु शकतात.

अ.क्र.	कामाचे नांव	रक्कम
१.	मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील गणेश नगर मालवणी, मालाड (पश्चिम) येथील जिल्हा सैनिक मुलांच्या वसतीगृह इमारतीच्या कुंपण भिंतीची दुरुस्ती करणे.	रु.४२,९७,९३०/-
२	मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील गणेश नगर मालवणी, मालाड (पश्चिम) येथील जिल्हा सैनिक मुलांच्या वसतीगृह इमारतीचे प्लास्टर करणे, आतून व बाहेरून रंगरंगोटी करणे	रु.४९,९९,३९०/-
३	मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील गणेश नगर मालवणी, मालाड (पश्चिम) येथील जिल्हा सैनिक मुलांच्या वसतीगृह इमारतीच्या जोत्याची (Plinth Protection) दुरुस्ती करणे.	रु.२७,८५,७४८/-
४.	मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील गणेश नगर, मालाड पश्चिम मुंबई जवळील मालवणी येथील सैनिक बॉईज हॉस्टेलच्या टेरेसवर जी. आय. शीट्ससह नवीन स्ट्रक्चरल स्टील शेडचे बांधकाम	रु.१८,७८,२६०/-

ई-निविदा वेळापत्रक

१	निविदा डाऊनलोड करण्यांचा कालावधी	दिनांक **१३ /१०/२०२५@ १५:००** पासून दिनांक **२०/१०/२०२५** @ १७:०० पर्यंत.
२	निविदा सादर करण्याचा कालावधी	दिनांक १३/**१०/२०२५** @१५:०० पासून दिनांक **२०/१०/२०२५** @ १७:०० पर्यंत.
३	निविदा उघडण्याचे ठिकाण दिनांक व वेळ (शक्य झाल्यास)	दिनांक **२४/१०/२०२५** सकाळी १७:१५ वाजता (शक्य झाल्यास) कार्यकारी अभियंता, मार्ग विकास विभाग क्र.४, अंधेरी , ,मुंबई-४०००५८ यांचे कार्यालय

खालील संकेतस्थळावर ई निविदाची सर्व माहिती उपलब्ध आहे.

१. https://mahapwd.com
२. https://mahatenders.gov.in
(सदर निविदेसुचनामध्ये काही बदल होत असल्यास वरील वेबसाईट वरती कळविण्यांत येईल.)
३. कार्यकारी अभियंता, मार्ग विकास विभाग क्र.४, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-४०००५८. कार्यालयातील सूचना फलक.

स्थळप्रत- का.अ.यांनी मंजूर केली आहे.

जा.क्र. का.अ.माविवि.क्र.४/ निविदा/६१०
कार्यकारी अभियंता,यांचे कार्यालय,
मार्ग विकास विभाग क्र. ४, प्रशासकीय इमारत,
३ रा मजला ,भवन्स कॉलेजजवळ, दादाभाई नौरोजी मार्ग,
अंधेरी, मुंबई, ४०० ०५८.
दिनांक :- **०८/१०/२०२५**

कार्यकारी अभियंता,
मार्ग विकास विभाग क्र.४,
अंधेरी , मुंबईकरीता

DGIPR/2025-26/3094

यहां समझौता करने नहीं आए, कॉनराड संगमा ने मणिपुर में अलग प्रशासन की बातों को किया खारिज

इम्फाल **(एजेंसी)**। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने मणिपुर में अलग प्रशासन की किसी भी मांग के खिलाफ अपने और नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के रुख को दृढ़ता से दोहराया है। संगमा वर्तमान में राज्य में शांति के लिए सुझाव मांगने हेतु नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और सामुदायिक नेताओं से मिलने मणिपुर का दौरा कर रहे हैं। उनकी यह टिप्पणी मणिपुर में चल रहे तनाव के बीच आई है, जहाँ अलग-अलग मांगों और सामुदायिक चिंताओं ने क्षेत्र की शांति को खतरे में डाल दिया है। इम्फाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम यहां मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता करने नहीं आए हैं। राज्य के भीतर प्रशासनिक ढांचे कैसे काम कर सकते हैं, इस पर हमेशा चर्चा हो सकती है, लेकिन मणिपुर को पूरी तरह से विभाजित करना हमारा रुख नहीं है।

संगमा ने सभी समुदायों से सार्थक संवाद में शामिल होने की अपील की और कठोर रुख अपनाने के प्रति आगाह किया जो दुख को और बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा अगर हम अपने रुख पर अड़े रहेंगे और मुद्दों पर ध्यान नहीं देंगे, तो हम कहीं नहीं पहुँच पाएँगे। संवाद और समझ आगे बढ़ने की कुंजी हैं। कई नागा नागरिक समाज संगठनों द्वारा मुक्त आवागमन व्यवस्था (एफएमआर) और सीमा बाड़ लगाने के बारे में उठाई गई चिंताओं के जवाब में संगमा ने व्यापक परामर्श की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने केंद्र से निर्णय लेने से पहले स्थानीय समुदायों के साथ बातचीत करने का आग्रह किया और कहा राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। जब बातचीत खुली होती है तो आगे बढ़ने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर विचार-विमर्श के दौरान पिछले परामर्शों से तुलना की। संगमा ने मौजूदा संकट से निपटने के लिए एनपीपी द्वारा उठाए गए कदमों का ज़िक्र किया, जिसमें विश्वास बहाली के उपायों की वकालत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से औपचारिक संवाद भी शामिल है। उन्होंने कहा कि करीब डेढ़ साल पहले, हमने गृह मंत्रालय को लिखा था कि विश्वास बहाली के लिए कुछ किया जाना चाहिए। लोगों का नेतृत्व पर से भरोसा उठ गया था। पार्टी ने इससे पहले राजनीतिक गठबंधनों पर जनहित को प्राथमिकता देते हुए पिछली भाजपा-नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।

दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की मिलेगी इजाजत? सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे मेहता ने शीर्ष अदालत से दीपावली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे अवसरों पर दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति देने का आग्रह किया।

केंद्र सरकार ने अदालत से अतिरिक्त समय मांगते हुए कहा था कि वह सभी हितधारकों से परामर्श के बाद एक रिपोर्ट पेश करेगी। 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नीरी (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान) और पेसो (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) प्रमाणित हरित पटाखों के निर्माण की अनुमति दे दी थी। हालाँकि, कोर्ट ने यह भी कहा था कि उसकी अनुमति के बिना ये पटाखे एनसीआर में नहीं बेचे जा सकते। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पटाखा निर्माताओं के वकील बलबीर सिंह ने अनुरोध किया है कि सुनवाई दिवाली से पहले की जाए।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अदालत से हरित पटाखों पर छूट देने का आग्रह किया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा है कि दिवाली एक सांस्कृतिक त्योहार है और जनता की भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया है कि सभी संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। इससे पहले, 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। पीठ ने निर्माताओं को यह भी निर्देश दिया था कि जब तक अदालत कोई नया आदेश जारी नहीं करती, तब तक वे एनसीआर में कोई भी पटाखा न बेचें। अदालत ने कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध न तो संभव है और न ही सही। हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वह दिल्ली सरकार, पटाखा निर्माताओं और विक्रेताओं सहित सभी हितधारकों से बात करे और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आए। ऐसा व्यावहारिक समाधान लेकर आए जो सभी को स्वीकार्य हो। बाद में 3 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध को सर्दियों के मौसम तक सीमित रखने के बजाय पूरे साल के लिए बढ़ा दिया। यह फैसला फिलहाल अदालत में चुनौती के अधीन है।

पवन सिंह विवाद : प्रशांत किशोर से मिलीं ज्योति सिंह कहा- राजनीति नहीं, महिलाओं की आवाज़ बनूंगी

पटना **(एजेंसी)**। भोजपुरी गायक-अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से मिलने पटना के शेखपुरा हाउस पहुंचीं। इसके बाद ज्योति सिंह की मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई। मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने कहा कि मैं यहाँ चुनाव लड़ने या टिकट मांगने नहीं आई हूँ, मैं यह सुनिश्चित करने आई हूँ कि किसी और महिला को मेरे जैसा अन्याय न सहना पड़े। मैं ऐसी सभी महिलाओं की आवाज़ बनना चाहती हूँ। इसलिए मैं प्रशांत भैया से मिली। चुनाव या टिकट पर कोई चर्चा नहीं हुई। मैं यहाँ सिर्फ़ उन सभी महिलाओं के लिए आई हूँ।

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि ज्योति जी एक बिहारी और एक महिला के तौर पर यहाँ आई थीं। हमने उनकी बात सुनी। सबसे पहले, उन्होंने चुनाव लड़ने के बारे में कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि चुनाव लड़ना या टिकट पाना उनका मकसद नहीं है। उनके अपने शब्दों में, उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है। वह चाहती हैं कि उनके साथ जो हुआ, वह बिहार की किसी और महिला के साथ न हो। वह जन सुराज से मदद चाहती हैं। मैंने उन्हें बताया है कि प्रशांत किशोर की उनके पारिवारिक मामलों में कोई भूमिका नहीं हो सकती, लेकिन मैंने उनसे यह भी कहा है कि जहाँ तक उनकी सुरक्षा या लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है।

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जन सुराज उनके साथ है, उन्हें कानूनी तरीके से लड़ना चाहिए। पवन सिंह मेरे भी दोस्त हैं। मैं उनके पारिवारिक मामले में कुछ नहीं कह सकता। अगर वह मेरे पास आई हैं, तो उनसे मिलना और उनकी बात सुनना मेरी सामाजिक ज़िम्मेदारी है। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं माँगा है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह अपनी चल रही कानूनी लड़ाई के बीच मीडिया में बयानबाजी के साथ सार्वजनिक विवादों में घिर गए हैं। ज्योति द्वारा गर्भपात की गोलियाँ लेने के लिए मजबूर करने सहित गंभीर दुर्व्यवहार का आरोप लगाने के बाद विवाद और गहरा गया है, जबकि पवन ने सभी आरोपों को झूठा बताते हुए अपना पक्ष रखा है।

काबुल पर वार, दिल्ली की चाल और आतंक का नया चेहरा, South Asia में बिछी नई राजनीतिक शतरंज

नई दिल्ली।जैसे ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत की धरती पर उतरे, इस्लामाबाद बेचैन हो उठा। दिल्ली-काबुल के बीच कूटनीतिक संवाद गहराया और उसी समय पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई हमले कर डाले। यह संयोग नहीं, संकेत है। दक्षिण एशिया में नई राजनीतिक शतरंज बिछ चुकी है। भारत अपनी भूमिका को नए सिरे से गढ़ रहा है और पाकिस्तान अपनी पुरानी 'रणनीतिक गहराई' खोने के डर से बौखला उठा है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी विमानों ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन असल संदेश अफगान सरकार और भारत दोनों को था कि इस्लामाबाद अब अपने 'सुरक्षा क्षेत्र' में किसी और को दखल नहीं करने देगा। यह वही पाकिस्तान है जो एक ओर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का दावा करता है और दूसरी ओर उन्हीं संगठनों को खुला संरक्षण देता है जिनसे पूरा क्षेत्र अस्थिर होता है।

इसी बीच, एक और चौंकाने वाली खबर आई है कि Jaish-e-Mohamme ने अपनी महिला शाखा 'Jamaat-ul-Mominaat' का गठन किया है, जिसका नेतृत्व खुद मसूद अजहर की बहन सदिया को सौंपा गया है। यह आतंक की रणनीति में नया और खतरनाक मोड़ है यानि 'जिहाद का नारीकरण'। महिलाओं को पर्दे के पीछे से वैचारिक और संगठनात्मक जिम्मेदारियाँ देकर आतंकवादी नेटवर्क अब समाज की नई परतों में प्रवेश कर रहे हैं। यह न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है, बल्कि यह चरमपंथ को वैचारिक वैधता देने की सोची-समझी कोशिश भी है।

वहीं, भारत और अफगानिस्तान के बीच वार्ता ने नई दिल्ली की अफगान नीति को नया आयाम दिया है। भारत ने काबुल में अपने मिशन को पूर्ण दूतावास में उन्नत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। देखा जाये तो यह स्पष्ट संदेश है कि भारत न केवल मानवीय सहायता बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता की राजनीति में भी निर्णायक भूमिका निभाना चाहता है। पाकिस्तान को यह रास नहीं आ सकता। इन तीनों घटनाओं– अफगान वार्ता, पाकिस्तानी हमले और जमाअत-उल-मोमिनात के गठन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिण एशिया में सत्ता, सुरक्षा और रणनीति का समीकरण तेजी से बदल रहा है। भारत जहाँ कूटनीतिक परिपक्वता दिखा रहा है, वहीं पाकिस्तान अब भी पुराने डर और असुरक्षा में उलझा है। इसलिए सवाल यही है कि क्या यह क्षेत्र संवाद और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ेगा, या फिर एक बार फिर 'आतंक, अविश्वास और अस्थिरता' की उसी पुरानी लय में लौट जाएगा? जवाब आने वाला समय देगा, पर संकेत साफ हैं कि भारत शांत रहकर खेल जीतना चाहता है, जबकि पाकिस्तान शोर मचाकर हार रहा है।

भारत का बड़ा फैसला, काबुल में फिर से खुलने जा रहा भारतीय दूतावास

काबुल **(एजेंसी)**। तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस समय एक सप्ताह की भारत यात्रा पर हैं। शुक्रवार, 10 अक्टूबर को उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की, जिसके बाद भारत ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घोषणा की। जयशंकर ने कहा कि अब काबुल में मौजूद टेक्निकल मिशन को भारतीय दूतावास का दर्जा दे दिया जाएगा।

दरअसल, 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद भारत ने सुरक्षा कारणों से काबुल स्थित दूतावास बंद कर दिया था। इसके बाद व्यापार, चिकित्सा और मानवीय सहायता के लिए एक छोटा तकनीकी मिशन स्थापित किया गया था। अब भारत ने इसे पूर्ण दूतावास के रूप में बहाल कर दिया है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा देने वाला कदम है. उन्होंने अफगानिस्तान के विकास और स्थिरता के प्रति भारत की लगातार प्रतिबद्धता को दोहराया।

जयशंकर ने कहा, 'भारत और अफगानिस्तान विकास और समृद्धि के प्रति समान रूप से समर्पित हैं, लेकिन यह प्रतिबद्धता सीमा पार आतंकवाद के साझा खतरे से प्रभावित होती है. हमें इसके सभी रूपों से निपटने के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे. हम भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझने के लिए अफगान पक्ष की सराहना करते हैं।' उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले

के बाद अफगानिस्तान द्वारा जताई गई एकजुटता को 'उल्लेखनीय' बताया।

जयशंकर ने मुलाकात के दौरान खेल के जरिए दोनों देशों के जुड़ाव की भी चर्चा की। उन्होंने कहा, 'अफगानिस्तान में क्रिकेट प्रतिभा का उदय प्रभावशाली रहा है। भारत अफगान क्रिकेट को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।'

बैठक के अंत में जयशंकर ने कहा कि भारत, अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने घोषणा की- 'काबुल में भारत के तकनीकी मिशन को अब भारतीय दूतावास का दर्जा दिया जा रहा है। यह निर्णय दोनों देशों के गहरे सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।'

भारत भले ही अभी तक तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता नहीं देता, लेकिन दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है। मुत्ताकी की यह यात्रा नई दिल्ली और काबुल के बीच भरोसे की नई कड़ी मानी जा रही है।

हाल ही में भारत ने रूस, चीन और सात अन्य देशों के साथ मिलकर अफगानिस्तान में किसी भी विदेशी सैन्य ढांचे की तैनाती का विरोध किया था। इन देशों ने संयुक्त रूप से कहा कि वे अफगानिस्तान को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रणाली से सक्रिय रूप से जोड़ने का समर्थन करते हैं।

भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि अफगान धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। इसी वर्ष मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जयशंकर और मुत्ताकी के बीच फोन पर हुई बातचीत में तालिबान ने पहलगाम हमले की निंदा की थी. जनवरी में, तालिबान शासन ने भारत को 'महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और आर्थिक शक्ति' करार दिया था।

भारत-ब्रिटेन ने 468 मिलियन डॉलर का 'गेमचेंजर' रक्षा समझौता किया, सेना को मिलेगी नई ताकत

नई दिल्ली। अपने सशस्त्र बलों को मज़बूत और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से, भारत ने हल्के बहुउद्देशीय मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ 468 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई में अपने ब्रिटिश समकक्ष कीर स्टारमर से मुलाकात के बाद हुआ है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस समझौते से न केवल भारत को मदद मिलेगी, बल्कि ब्रिटिश रक्षा उद्योग को उत्तरी द्वीप में 700 से ज़्यादा नौकरियाँ पैदा करने में भी मदद मिलेगी। मंत्रालय ने आगे कहा कि यह समझौता ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापक जटिल हथियार साझेदारी का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा इस अनुबंध के तहत भारतीय सेना को बेलफास्ट में निर्मित ब्रिटेन निर्मित हल्के बहुद्देशीय मिसाइल (एलएमएम) दिए जाएंगे, जो ब्रिटेन के रक्षा उद्योग के लिए एक और महत्वपूर्ण बढ़ावा होगा और सरकार की बदलाव की योजना को पूरा करेगा। भारत के लिए निर्मित किए जा रहे वायु रक्षा मिसाइल और लांचर वही हैं जो वर्तमान में यूक्रेन के लिए बेलफास्ट में उत्पादित किए जा रहे हैं। हल्के वजन वाली बहुउद्देशीय मिसाइल, जिसे लोकप्रिय रूप से मार्टल नामक एक पौराणिक पक्षी के नाम से जाना जाता है। थेल्स एयर डिफेंस द्वारा विकसित किया गया है। इन मिसाइलों का वज़न 13 किलोग्राम है, जबकि इनकी गति ध्वनि की गति से 1.5 गुना ज़्यादा है। ये मिसाइलें ज़मीन और हवा, दोनों जगह, 6 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य पर वार कर सकती हैं। हालाँकि, इन मिसाइलों का इस्तेमाल आमतौर पर वायु रक्षा अभियानों के लिए किया जाता है।

थेल्स एयर डिफेंस ने इस मिसाइल को विशेष रूप से रॉयल ब्रिटिश नेवी की 'भविष्य की हवा से सतह पर मार करने वाले निर्देशित हथियार (हल्के)' की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया था। मार्टल, जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश सशस्त्र बल 2019 से कर रहे हैं, का इस्तेमाल हाल ही में यूक्रेनी सेना ने रूस के खिलाफ युद्ध में किया था।

फिलीपींस में 7.2 की तीव्रता का भयंकर भूकंप, तेज झटकों से लोगों में दहशत, सुनामी का अलर्ट जारी

मिंडानाओ **(एजेंसी)**। फिलीपींस में शुक्रवार सुबह भूकंप के तेज झटकों से लोग दहशत में आ गए। स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 9 बजकर 43 मिनट पर दक्षिणी द्वीप मिंडानाओ में धरती कांप उठी। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई है। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि समुद्र में एक मीटर से ऊंची लहरें उठने की संभावना जताई गई है। इसी के चलते सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है।

भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। प्रशासन ने समुद्र तट के पास रहने वाले लोगों को ऊंचे इलाकों की ओर जाने की सलाह दी है। मिंडानाओ और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा असर देखा गया है। राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच चुके हैं। अब तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन कई इलाकों में इमारतों और दीवारों में दरारें आने की सूचना मिली है।

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप का केंद्र समुद्र में लगभग 10 से 58 किलोमीटर की गहराई पर था। वहीं यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंपीय केंद्र ने भूकंप की तीव्रता 7.4, और फिलिपीन एजेंसी फिलवोल्क्स ने 7.6 दर्ज की है। यानी अलग-अलग एजेंसियों के मुताबिक भूकंप बेहद शक्तिशाली था।

फिलवोल्क्स ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले घंटों में ऑफ्टरशॉक्स (भूकंप के बाद आने वाले झटके) महसूस किए जा सकते हैं। अधिकारियों ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने की अपील की है। स्थानीय प्रशासन लगातार तटीय इलाकों पर नजर बनाए हुए है और सुनामी की स्थिति में तुरंत निकासी की तैयारी कर ली गई है।फिलीपींस भूकंपीय दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। यह देश प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' ज़ोन में आता है, जहां ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। पिछले कुछ वर्षों में यहां कई बार 6 से ऊपर की तीव्रता वाले भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं।

5 घंटे में पूरा पाकिस्तान खा गई भारतीय सेना, कई देशों में हड़कंप

इस्लामाबाद **(एजेंसी)**। भारतीय वायु सेना ने पहली बार पाकिस्तान पर ऐसा हमला किया है, जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में किया जाएगा। भारत के साथ साथ दुनिया भी इस बात से हैरान है कि कैसे पांच घंटे के अंदर डिनर में पूरा पाकिस्तान भारतीय सेना प्लेट में रखकर खा गई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केवल 180 मिनट में पाकिस्तानी वायु सेना के 20 प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने वाली भारतीय वायुसेना ने एक ऐसा खेल कर दिया है जो हर किसी के होश उड़ा देगा। दरअसल, भारतीय वायु सेना की 93वीं वर्षगांठ 8 अक्टूबर को मनाई गई। इस मौके पर आयोजित जश्न की डिनर मेन्यू की तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई। मेन्यू में चुटीले अंदाज के जरिए पाकिस्तान पर हल्का-फुल्का व्यंग्य किया गया है। डिनर में परोसी गई डिशेज के नाम पाकिस्तान के उन जगहों पर थे, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान निशाना बनाया गया था।

भारतीय वायुसेना को परोसे गए व्यंजनों में 2019 का बालाकोट हवाई हमला और हालिया ऑपरेशन सिंदूर शामिल है। वायरल हुई तस्वीर में कई मजेदार नाम वाले व्यंजन दिखाई दिए, जैसे रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, रफीकी रहारा मटन, भोलारी पनीर मेथी मलाई, सुक्कुर शाम सवेरा कोफ्ता, सरगोधा दाल मखनी, के बाद बारी जकोकाबाद की थी। जकोबाबाद में ही अमेरिका के एफ 16 लड़ाकू विमान खड़े थे। फिर बहावलपुर नान का नंबर आया। आपको बता दें कि बहावलपुर जैश के आतंकी मसूद अजहर का हेडक्वार्टर था। आईएएफ के इस अंदाज ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा और लोगों ने इसे रचनात्मक और चुटीले तरीके से देशभक्ति दिखाने वाला बताया। मेन्यू ने सैन्य इतिहास और हवाई हमलों को हल्के अंदाज में पेश करते हुए युवाओं के बीच भी लोकप्रियता हासिल की। इस प्रकार, वायु सेना का जश्न सिर्फ सैन्य गौरव का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि यह इंटरनेट पर हास्य और क्रिएटिविटी के कारण चर्चा में भी आ गया।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)